राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 07 मार्च 2026 वर्ष-9,अंक-41 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

● कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सीएम सिद्धा ने किया ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर पर को कम करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही है। सीएम सिद्धारमैया ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 4.48 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में टेक्नोलॉजी से चलने वाली लर्निंग पहलों को रेगुलेटरी उपायों के साथ मिलाकर सुधारों का ऐलान किया गया है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा

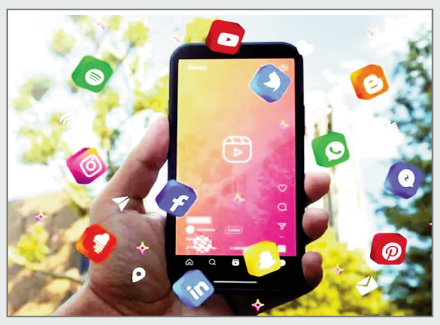

दी जा सके। सीएम सिद्धारमैया ने राज्य में 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात कही है। राज्य में जब यह नियम लागू होगा, तब कर्नाटक बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा,बच्चों पर बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड लर्निंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार क्लास 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के साथ मिलकर बनाया गया एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम शुरू करेगी। इस प्रोग्राम से लगभग 1.22 मिलियन स्टूडेंट्स को फायदा होने की उम्मीद है और इसे 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से इस साल 100 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया है।

भारत में संकट, रसोई गैस इमरजेंसी लागू

● सरकार ने सभी तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया ● ईरान-इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान-इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ेगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। यानी इन गैसों का उपयोग किसी और काम में नहीं किया जाएगा।

● **कतर में गैस उत्पादन बंद, भारत में सप्लाई घटी-** मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिडिल-ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का प्रोडक्शन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40 फीसदी तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40 फीसदी एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो संकट बढ़ सकता है।

सरकारी कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता

आदेश के मुताबिक, सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को करनी होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के लगभग 33.2 करोड़ एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर मिलते रहें। सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का डायवर्जन होने से अल्काइलेट्स के प्रोडक्शन में कमी आएगी, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल की ग्रेडिंग सुधारने में किया जाता है। पिछले साल रिलायंस ने हर महीने एवरेज चार अल्काइलेट्स कार्गो एक्सपोर्ट किए थे।

रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत

ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय

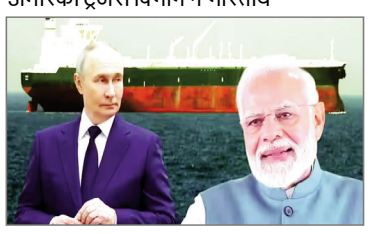

रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर हैं और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है।

इजराइल-अमेरिका का वार

ईरान का पलटवार

● ईरान के शिराज शहर पर भीषण हमला,20 की मौत ● ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका का ड्रोन गिराया

तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का शुक्रवार को सातवां दिन था। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के शिराज शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक यह हमला शहर के जीबाशहर इलाके के रिहायशी क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई आम लोग मारे गए। इस हमले में दो मेडिकल कर्मचारियों की भी मौत हो गई। वहीं ईरानी सेना ने लोरेस्तान इलाके में अमेरिका का एमक्यू-9 ड्रोन और इजराइल का आईजे-900 ड्रोन को

मार गिराया है। जंग की वजह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। फ्रांस के परिवहन मंत्री ने कहा कि फारस की खाड़ी में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं और 8 जहाज रेड सी में रुके हुए हैं।

ईरान के हमले में यूएई-जॉर्डन को भारी नुकसान

मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले से संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इन देशों के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, जो कि अमेरिका के बनाए हुए थे। अरब पेनिनसुला के मिलिट्री बेस से मिली नई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने वाले यूएस-मेड रडार को खत्म करके एयर डिफेंस को कमजोर कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड अरब अमीरात में दो जगहों पर ऐसे ही रडार सिस्टम वाली बिल्डिंग्स पर भी हमला हुआ, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि इक्विपमेंट डैमेज हुआ या नहीं।

अमेरिकी सैनिकों के लिए दलदल बन जाएगा ईरान

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के

जमीनी हमले के लिए तैयार है। अराघची की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में जमीनी अभियान के लिए सैनिक उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने सीजफायर के लिए नहीं कहा है। ईरानी विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के जमीनी हमले का डर है, तो उन्होंने कहा,नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं।

यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी

● राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर, 958 कैंडीडेट्स क्वालिफाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडीडेट्स अलग-अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जारी रिजल्ट में कुल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए चयनित हुए हैं।

यूपीएससी सिविल सर्विस 2026 प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित की गई थी। इसके बाद मेन्स एग्जाम 22 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। चयनित उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, 27 फरवरी 2026 को खत्म हुए थे। भारत सरकार ने कैडर अलॉटमेंट के लिए 2017 से चली आ रही जोन सिस्टम की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसकी जगह नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है।

इसके तहत अब साइकिल सिस्टम के जरिए अफसरों के कैडर का बंटवारा होगा। ये पॉलिसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए चयनित उम्मीदवारों पर लागू होगी। यूपीएससी ने अब तक सभी स्टेट और यूटी के कुल 25 कैडर बनाए थे। इन्हें जियोग्राफिकली 5 जोन में बांटा गया था- नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट। यूपीएससी मेन्स क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स फॉर्म भरते थे जिसमें पहले जोन और फिर स्टेट प्रिफरेंस चुनने का मौका मिलता था। एक बार जिस स्टेट में ऑफीसर की नियुक्ति होती है, परमानेंट उसी स्टेट में काम करना होता है। इसे ही कैडर कहते हैं।

छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की तैयारी में भारत!

● बड़ा है प्लान,अभी अमेरिका और चीन के पास भी नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक योजना पर काम शुरू कर सकता है। इसके तहत यूरोप के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में शामिल होने की बात है। रिपोर्ट है कि भारत इस कार्यक्रम के तहत फ्रांस और जर्मनी के साथ साझेदारी करने की तैयारी में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्तर पर हाल ही में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर पहल किए जाने के संकेत मिल चुके हैं। इस दौरान डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की योजना पर अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है। भारतीय वायु सेना को अत्याधुनिक फाइटर जेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारत में पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने पर पहले से ही

काम चल रहा है। लेकिन, इसके साथ-साथ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर भी चर्चा शुरू की गई है। इस समय अमेरिका और चीन की ओर से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर काम चल रहा है। लेकिन, किसी ने भी इसे बना लेने का दावा नहीं किया है। इसी तरह के मिशन पर जर्मनी और फ्रांस भी लगे हैं, लेकिन यूरोप में मौजूदा अस्थिरता की वजह से इसका विकास फंसा हुआ है और यही भारत के लिए अवसर बनकर उभरा है।

जदयू कार्यालय में पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती

● बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का विरोध हुआ तेज

पटना (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विरोध तेज हो गया है। पटना स्थित जदयू के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए और नीतिश के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। जदयू कार्यालय में लगे पोस्टर में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिख भी पोत दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतिश से राज्यसभा जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। शुक्रवार सुबह से पटना में जदयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जदयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और बैनर लगाकर नारेबाजी करने लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह बिहार के जनादेश का अपमान है। बिहार की जनता ने नीतिश कुमार के नाम पर वोट दिया था। उनके चेहरे पर बिहार विधानसभा का

चुनाव लड़ा गया था। इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए वही पात्र हैं। जदयू कार्यकर्ताओं ने जदयू अध्यक्ष एवं सीएम नीतिश कुमार से राज्यसभा जाने का फैसला वापस लेने की मांग की है।

भारतीय वायुसेना का ताकतवर विमान एसयू-30 क्रैश

● जोरहाट से भरी थी उड़ान, फिर रडार से हो गया गायब

गुवाहाटी (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान गुरुवार रात असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन (ट्रेनिंग मिशन) पर था। वायुसेना के अनुसार, विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और शाम करीब 7.42 बजे इसका रडार और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह विमान जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग इलाके में दुर्घटना का शिकार हुआ है। वायुसेना ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि विमान तय समय पर वापस नहीं लौटा है। घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू मिशन यानी खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और फिलहाल इलाके में युद्धस्तर पर तलाश जारी है। विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है। सुखोई एसयू-30 एमकेआई सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों से यह भारतीय वायुसेना की रीढ़ और भारत की हवाई ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है।

सुखोई के बिना आधुनिक भारतीय वायुसेना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 90 के दशक के मध्य में भारतीय वायुसेना को एक ऐसे भारी और लंबी दूरी के लड़ाकू विमान की तलाश थी, जो एयर सुपीरियरिटी (हवाई वर्चस्व) स्थापित कर सके। 30 नवंबर 1996 को भारत ने रूस के साथ 50 सुखोई-30 विमानों की खरीद के लिए 1.46 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत केवल साधारण सुखोई नहीं चाहता था, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से एक उन्नत विमान चाहिए था।

यहीं से एसयू-30 एमकेआई का जन्म हुआ। एसयू का रूसी भाषा में मतलब है- डर्निजिरोवन्नी कोमर्स्चेस्की इंडिस्की यानी आधुनिक व्यावसायिक भारतीय संस्करण। यह एक ट्विन-सीटर (दो सीटों वाला) उन्नत लड़ाकू विमान है।

इसे मूल रूप से रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 200 से अधिक एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल हैं। सुखोई दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू विमान है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को हवा से दाग सकता है। इसके लिए आईएएफ ने विमान के ढांचे में विशेष बदलाव किए थे। हाल के वर्षों में सुखोई को भारत की स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल से भी लैस किया गया है, जिसने इसे हवा से हवा में मार करने में और भी खतरनाक बना दिया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 260-270 एसयू-30 एमकेआई विमानों का बेड़ा है, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर विभिन्न एयरबेस पर तैनात हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अन्न से आत्मनिर्भरता तक: विश्व अनाज दिवस का संदेश

इतिहास की दृष्टि से जौ को दुनिया के सबसे प्राचीन खेती किए गए अनाजों में से एक माना जाता है, जिसके प्रमाण लगभग 10,000 वर्ष पुराने मिलते हैं। इतिहासकारों का मत है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं का विकास कृषि, विशेष रूप से अनाज उत्पादन, के कारण ही संभव हुआ।

(लेखक- सुनील कुमार महला)

(7 मार्च दिवस विशेष आलेख)

अनाजों के महत्व, पोषण और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 मार्च को विश्व अनाज दिवस (वर्ल्ड सीरियल डे) मनाया जाता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि 'सीरियल' शब्द की उत्पत्ति प्राचीन रोमन देवी सेरेस के नाम से हुई है। दरअसल, रोमन पौराणिक कथाओं में सेरेस को खेती, फसल और मातृत्व की देवी माना जाता था और उन्हीं के सम्मान में अनाज को 'सीरियल' कहा जाने लगा। वैसे, गेहूं, चावल, मक्का, जौ और जई जैसे खाद्यान्न सीरियल्स की श्रेणी में आते हैं।

विश्व अनाज दिवस वस्तुतः खाद्य सुरक्षा की नींव को रेखांकित करता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ और बाजरा जैसे अनाज केवल भोजन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। उल्लेखनीय है कि आज विश्व की आधी से अधिक आबादी की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताएँ मुख्यतः तीन अनाजों-गेहूं, चावल और मक्का से ही पूरी होती हैं। यदि अनाज न हों, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कल्पना भी संभव नहीं। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और भूख जैसी चुनौतियों का लगातार सामना कर रही है, तब अनाजों का महत्व और बढ़ जाता है। आज तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और सूखा जैसी परिस्थितियाँ विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ अपनाना समय की आवश्यकता है।

भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा देश विश्व के प्रमुख गेहूं और चावल उत्पादक देशों में शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से करोड़ों लोगों तक सस्ती दरों पर अनाज पहुँचाया जाता है। हाल के वर्षों में मोटे अनाज-जैसे बाजरा, ज्वार और रागी आदि को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' घोषित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के महत्व को नई पहचान मिली।

विश्व अनाज दिवस का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि अनाजों के पोषण मूल्य, खाद्य अपव्यय रोकने, संतुलित आहार अपनाने और किसानों के परिश्रम के सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। वास्तव में यह दिवस कुपोषण और भूख की समस्या को कम करने, टिकाऊ कृषि (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका को रेखांकित करता है।

इतिहास की दृष्टि से जौ को दुनिया के सबसे प्राचीन खेती किए गए अनाजों में से एक माना जाता है, जिसके प्रमाण लगभग 10,000 वर्ष पुराने मिलते हैं। इतिहासकारों का मत है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं का विकास कृषि, विशेष रूप से अनाज उत्पादन, के कारण ही संभव हुआ।

आज बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाजों को 'फ्यूचर फूड' कहा जा रहा है। ये प्रायः ग्लूटेन-रहित होते हैं और आयरन व कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी कुछ अनाज अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, 'पेरेनियल ग्रेन्स' (बारहमासी अनाज) ऐसी फसलें हैं जिन्हें हर वर्ष दोबारा बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनकी गहरी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और कार्बन अवशोषण में सहायक होती हैं।

पाठक जानते होंगे कि मक्का विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है, किंतु इसका बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष भोजन के बजाय एथेनॉल (ईंधन) और पशु आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व में उत्पादित अनाज का बड़ा भाग भंडारण और परिवहन के दौरान नष्ट हो जाता है। यदि इस अपव्यय को रोका जाए तो करोड़ों लोगों की भूख मिटाई जा सकती है।

19वीं सदी के अंत में डॉ. जॉन हार्वे केलॉग ने कॉर्नफ्लेक्स जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल का आविष्कार किया था। उनका उद्देश्य इसे सादा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में प्रस्तुत करना था, ताकि लोग अत्यधिक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बच सकें।

अनाज ऊर्जा, फाइबर, विटामिन और खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विश्व की बड़ी आबादी का मुख्य भोजन अनाज ही है, जिनमें गेहूं और चावल का उपभोग सर्वाधिक होता है। जलवायु परिवर्तन का अनाज उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और गंभीर हो सकती हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'विश्व खाद्य दिवस' प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। भोजन का अधिकार 1948 की सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम थी-बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ-साथ।

भारत में अन्न उत्पादन की स्थिति सुदृढ़ हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले दशक में देश का अन्न उत्पादन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है। इतना ही नहीं, फल और सब्ज़ियों का उत्पादन भी 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक बढ़ा है। भारत दूध और बाजरा (मिलेट्स) के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि मछली, फल और सब्ज़ियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। वर्ष 2014 के बाद से शहद और अंडे का उत्पादन दोगुना हो चुका है।

भारत सरकार की प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना; पीएम पोषण योजना; अंत्योदय अन्न योजना; राइस फोर्टिफिकेशन तथा प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड (पीएसएफ) शामिल हैं, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

इसी क्रम में 'विश्व दलहन दिवस' (वर्ल्ड पल्सेस डे) प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को 'अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष' घोषित किया था। दालें न केवल पोषण का केंद्र हैं, बल्कि 'क्लाइमेट-स्मार्ट' फसलें भी मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। इनके पौधों की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।

पर्यावरणीय दृष्टि से दालों का जल पदचिह्न(वाटर फुटप्रिंट) अत्यंत कम है।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जहाँ एक किलोग्राम बीफ उत्पादन में लगभग 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वहीं उतनी ही मात्रा में दाल उगाने के लिए केवल 50 से 200 लीटर पानी पर्याप्त होता है। पोषण के स्तर पर दालें प्रोटीन का सस्ता और प्रभावी स्रोत हैं। इनमें अनाज की तुलना में दो से तीन गुना अधिक प्रोटीन तथा आयरन, जिंक और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शून्य कोलेस्ट्रॉल और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये हृदय रोग और मधुमेह प्रबंधन में सहायक हैं।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विशिष्ट है। भारत विश्व की लगभग 25त्न दालों का उत्पादक और 27त्न उपभोक्ता है। वर्ष 2026 के हालिया आँकड़ों के अनुसार, भारत चना और मूंग जैसी प्रमुख दालों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। कभी 'गरीबों का प्रोटीन' कही जाने वाली दालें आज 'भविष्य का भोजन' मानी जा रही हैं।

अंततः, विश्व अनाज दिवस हमें यह संदेश देता है कि अनाज केवल भोजन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के दौर में इनका संरक्षण, टिकाऊ उत्पादन और खाद्य अपव्यय पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आइए, हर दाने का सम्मान करें और सुरक्षित, पोषित एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण का संकल्प लें।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

संपादकीय

अर्थव्यवस्था व विदेश नीति

'समरथ को नहिं दोष गुसाईं' उक्ति की तर्ज पर ईरान पर हुए अमेरिकी-इस्राइली हमले को पश्चिमी देशों द्वारा तार्किक बताया जा रहा है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई तथा उनके परिजनों समेत कई लोगों की मौत को किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यह समय वैश्विक कानून-व्यवस्था के भंग होने और अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों के सिरे चढ़ने का है। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने वैश्विक संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया की तमाम नियामक संस्थाओं को बेबस बना दिया है। वेनेजुएला में हमला करके राष्ट्रपति निकोलेस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाने के बाद अब खामेनेई की परिवार समेत हत्या ने दर्शा दिया है कि दुनिया फिर जंगल-राज की तरफ बढ़ रही है। शक्ति बंदूक की नोक से निकलती दिख रही है। छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता संकट में है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, वेनेजुएला व ईरान पर अमेरिकी हमला बता रहा है कि आने वाले दिनों में ताइवान जैसे अन्य संकटग्रस्त देशों के सामने अस्तित्व बनाये रखने की चुनौती होगी। पूरी दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला में आये व्यवधान तथा ट्रंप के टैरिफ आतंकवाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा रही है। रोजगार के अवसर कम हुए हैं और लोगों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पर अमेरिका-इस्राइल के हमले की प्रतिक्रिया मध्यपूर्व के अलावा पश्चिमी देशों में आने वाले समय में दिखाई देगी। जिसकी असली कीमत मानवता को ही चुकानी होगी। निस्संदेह, आने वाले दिनों में भारत को ईरान-अमेरिकी संघर्ष की कीमत चुकानी होगी। इससे भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत के लिये मुश्किल यह भी है कि ईरान पर हमला प्रधानमंत्री की इस्राइल यात्रा के तुरंत बाद हुआ है। जिससे भारत के लिये मध्यपूर्व को लेकर विदेश नीति में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इससे हार्मुज स्ट्रेट रूट से भारत को होने वाली कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं दूसरी ओर मध्यपूर्व में कार्यरत नब्बे लाख से अधिक भारतीयों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ेगा और उनके द्वारा भारत भेजी जाने वाली धनराशि भी प्रभावित होगी। भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल की पचास फीसदी आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट रूट से होती है। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव के चलते भी इस रूट से भारतीय आपूर्ति बढ़ी है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने का सीधा असर भारत में कच्चे तेलों के दामों पर पड़ेगा। भविष्य में भारतीयों को तेल कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। वहीं लाल सागर से होने वाली तेल आपूर्ति भी ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों की धमकी से प्रभावित होगी। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा। भारत इस समय ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का दावा करता है और फिलहाल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ईरान भी पिछले साल ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। ऐसे में क्या भारत इस हमले का विरोध करने की स्थिति में है? भारत ईरान से पुराने संबंधों के चलते क्या अमेरिका से दूरी बना सकता है?

नीतीश कुमार का राज्यसभा प्रस्थान : बिहार की राजनीति में नई करवट

(लेखक- बिनोद कुमार सिंह)

भारतीय राजनीति में कुछ घटनाएँ केवल सत्ता परिवर्तन की खबर नहीं होतीं,बल्कि वे एक पूरे दौर के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती हैं।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना भी ऐसी ही एक घटनाक्रम:है,जिसने बिहार की राजनीति पर पैनी पकड वालें राजनीतिक पंडितों में हलचल पैदा कर दी है। .लगभग दो दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे एक नेता का सक्रिय प्रशासनिक राजनीति से संसद भवन की ओर बढ़ना केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं है,बल्कि यह बिहार की राजनीति ,सत्ता संरचना,गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय रणनीति से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है।

नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का पर्याय रहे हैं। लगभग पाँच दशकों से अधिक का उनका राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र की अनेक परतों को अपने भीतर समेटे हुए है।उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के बख्तियारपुर में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति को अपना जीवन मार्ग बनाया।छात्र जीवन से ही वे राजनीति और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से अपनी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू की।1974 के जेपी आंदोलन ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को दिशा दी और यही आंदोलन आगे चलकर उन्हें बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित करने का आधार बना। सर्व विदित रहें कि

नीतीश कुमार पहली बार वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए।इसके बाद उनका राजनीतिक कद धीरे-धीरे बढ़ता गया।वर्ष 1989 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और संसद में उनकी सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई। 1990 के दशक में वे केंद्र की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे और कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सतही परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।रेल मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेख नीय रहा।वर्ष 1998 और 1999 के बीच तथा बाद में 2001 में उन्होंने रेल मंत्रालय का दायित्व संभाला। इसी दौरान बिहार के गयसाल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया।यह कदम उनकी राजनीतिक शैली और जवाबदेही की भावना का प्रतीक माना गया।

बिहार की राजनीति में उनका निर्णायक उदय वर्ष 2005 में हुआ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बनाई।उस समय बिहार लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहा था।नीतीश कुमार ने 'सुशासन' और विकास के एजेंडे के साथ सत्ता संभाली और राज्य की छवि बदलने का प्रयास किया।सड़कों के निर्माण,विद्यालयों में छात्राओं के लिए साइकिल योजना,महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे कदमों ने उन्हें एक विकासवादी नेता की पहचान दी। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक सफर भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। वर्ष 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि उस समय वे बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनका कार्यकाल केवल कुछ दिनों का रहा। इसके बाद वर्ष 2005 में वे पुनः मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक वे लगभग लगातार बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहे। 2005, 2010, 2015, 2020 और 2024 के बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच वे कुल मिलाकर दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।इस प्रकार लगभग बीस वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने बिहार की राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार-चढ़ाव भी आए।उन्होंने समय-समय पर गठबंधन बदले और राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ा।कभी वे भाजपा के साथ रहे,कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल हुए, और फिर दोबारा एनडीए के साथ लौट आए।यही कारण है कि उन्हें भारतीय राजनीति का एक अत्यंत व्यावहारिक और रणनीतिक नेता माना जाता है।अब जब उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है,तो यह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है।दो दशकों से अधिक समय तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहने के बाद उनका संसद की ओर बढ़ना केवल पद परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक भूमिका के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। उनके अनुसार संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनें। इसी क्रम में अब वे राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।इस निर्णय के साथ ही बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े हो गए हैं।सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अब किसके हाथ में जाएगी। पिछले बीस वर्षों में बिहार की राजनीति का एक स्थायी तथ्य यह रहा है कि गठबंधन चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अक्सर नीतीश कुमार ही दिखाई देते थे।ऐसे में उनके राज्यसभा जाने से सत्ता का नया समीकरण बनना लगभग तय माना जा रहा है।इस पूरे घटनाक्रम का राष्ट्रीय राजनीति से भी गहरा संबंध है।उनके नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री का पटना पहुँचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यह निर्णय केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। संभव है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका देने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया हो। संसद में उनकी उपस्थिति एनडीए के लिए एक अनुभवी और संतुलित नेतृत्व का प्रतीक बन सकती है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इसे जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है।उनका तर्क है कि यदि जनता ने किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और वह अचानक राज्यसभा की ओर चला जाता है तो यह लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है।वही दूसरी ओर एनडीए के नेता इसे नीतीश कुमार का व्यक्तिगत और स्वाभाविक निर्णय बता रहे हैं।राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस निर्णय के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। यदि बिहार में नया नेतृत्व उभरता है तो राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।भाजपा और जेडीयू के बीच सत्ता संतुलन का नया समीकरण भी बन सकता है।

प्रधानता आत्मा को

मनुष्य सामान्यतः जो बाह्य में देखता, सुनता, समझता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता। किन्तु भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार अपने कार्य करने केकारण मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख-शान्ति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। यथार्थ ज्ञान की अनुभावक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध, बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उसको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्यापसकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी तरह सत्, चित् एवं आनंद है, जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति संभव नहीं है उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश सम्भव नहीं। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती, सुनती और समझती है, वही सत्य और यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक-संतापों का स्वत- समाधान हो जाता है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है, किन्तु उसकी वाणी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की अन्तरात्मा बोलती है किन्तु मौन विचार स्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अन्तरात्मा की वाणी सुनने के लिए जरूरी है मनुष्य का मानसिक कोलाहल बन्द हो। अन्तरात्मा का सान्निध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यों मनुष्य की अन्तरात्मा उसमें ओतप्रोत है, पर उसका सच्चा सान्निध्य पाने के लिए उसे जानना आवश्यक है। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी होती है। रेलयात्रा में कन्धे से कन्धा मिलाये बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक-दूसरे से दूर होते हैं। अजनबी छोड़िए, जिन्दगी भर एक दूसरे केसाथ रहने पर भी आन्तरिक परिचय के अभाव में कई लोग एक-दूसरे से दूर ही रहते हैं। अन्तरात्मा जानने का एक ही उपाय है कि उसके विषय में सदा जिज्ञासु तथा सचेत रहा जाए। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है, वह उसकेविषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही उसे पा लेता है। आत्मा के विषय में अधिक से अधिकजिज्ञासु एवं सचेत रहिए। अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पाएंगे, तो अज्ञान से मुक्त हों यथार्थ सुख-शान्ति के अधिकारी बनेंगे।

विचार मंथन

इजरायल- ईरान की जंग के दो पाटों में फंसा भारत

(लेखक- सनत जैन)

- सास बहू की लड़ाई में.....

अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला करके सारी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया है। इसमें भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के आठवें दिन सबसे ज्यादा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। जिस लड़ाई से भारत का कोई लेना-देना नहीं था, उसी लड़ाई में भारत को इतना बड़ा नुकसान होगा, शायद यह भारत ने नहीं सोचा होगा। अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से भारत की सरकार को समझ आ रहा होगा। सास-बहू के झगड़े में जिस तरह से पति की स्थिति सबसे दयनीय होती है। ना तो वह अपनी मां के पक्ष में बोल पाता है, ना पत्नी के पक्ष में बोल पाता है। आज वही स्थिति भारत की इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच में देखने को मिल रही है। इजरायल द्वारा युद्ध के दूसरे ही दिन ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई और ईरान की पहली और दूसरी पंक्ति के नेताओं और सुरक्षा कमांडरों को निशाना बनाकर मार दिया गया। उसके बाद ईरान ने आर-पार की लड़ाई की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अमेरिका और इजरायल को ईरान की सैन्य ताकत के बारे में शायद सही अंदाजा नहीं था। जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा जोखिम मोल ले लिया, जो अब उनसे संभाले नहीं संभल रहा है। इजरायल ने ईरान के स्कूल में हमला करके 180 बच्चियों की सामूहिक हत्या की थी। उसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के तेलअबीब और येरूसलम को सबसे पहले निशाने में लिया उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और खाड़ी देशों में जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे थे, उन पर ईरानी मिसायलों से हमला किया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही, कि इजरायल का जो रक्षा सिस्टम था, वह ईरान की मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पाया। इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ इस तरह की स्थिति खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों की रही। जहां ईरान की मिसाइलें भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। रही-सही कसर ईरान ने हार्मोंज जल क्षेत्र से समुद्री जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया। जिसके कारण लगभग 30 फ़ीसदी देशों की तेल आपूर्ति और आयात निर्यात एक तरह से बंद हो गया है। अमेरिका द्वारा अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा नहीं कर पाने के कारण खाड़ी के देशों में भी दहशत फैल गई। रही-सही कसर अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को, जो भारत के साथ शांतिपूर्वक युद्ध अभ्यास के लिए आया हुआ था। उस जहाज को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सीमा, जो श्रीलंका के पास लगती है। उस पर अमेरिका ने हमला करके उसे डूबा दिया। जिसके कारण ईरान के 87 से अधिक सैनिक मारे गए। 32 से अधिक नौसैनिक घायल हो गए हैं। इसमें भारत की भूमिका सबसे ज्यादा नकारात्मक रही है। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर थे। उन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया था। उनके वापस आते ही ईरान के ऊपर हमला हो गया। शिया समुदाय के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के साथ-साथ लगभग दो दर्जन ईरान के कमांडरों की सामूहिक हत्या इजरायल द्वारा कर दी गई। उसके बाद भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ईरान को शोक संदेश भी नहीं भेजा गया, जिसके कारण भारत के ईरान के साथ जो संबंध थे, वह खराब हो गए। खाड़ी देशों में ईरान का हमला होने के कारण भारत के लगभग एक करोड़ लोग जो खाड़ी के देशों में नौकरी और रोजगार के लिए गए हुए थे, वह सब खतरे में पड़ गए हैं। रही सही कसर यूएई में पूरी हो रही है। भारत का सबसे ज्यादा निवेश यूएई के दुबई में लाखों करोड़ों डॉलर का है। लाखों लोग वहां काम कर रहे हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान दुबई को पहुंचाया है। जिसके कारण भारतीयों का निवेश वहां पर खतरे में पड़ गया है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी, उसमें रुस से तेल लेने का अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में से प्रतिबंध लगाया है। इस स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार को अमेरिका से रुस से कच्चे तेल और गैस आयात करने की अनुमति मांगनी पड़ी है। ईरान ने रूस और चीन के समुद्री जहाजों की आवाजाही को छूट दे रखी है। युद्ध के आठवें दिन भारत की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक पराजय है। भारत में विपक्षी दल और दुनिया के अन्य देश भारत को इजरायल और अमेरिका का पिट्ठू मान रहे हैं। एक तरह से वैश्विक राजनीति में भारत अलग-थलग पड़ गया है। इराक के बाद यदि सबसे बड़ा नुकसान किसी देश को होने जा रहा है, तो वह भारत है। भारत का शेयर बाजार निरंतर गिरता चला जा रहा है। भारत के पास 15 दिन से ज्यादा का कच्चा तेल और गैस उपलब्ध नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा है। जिस तरह की स्थितियां वैश्विक स्तर पर बन रही हैं, उसमें भारत भी युद्ध के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है? स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैश्विक राजनीति में भारत इतना कमजोर है। अब विपक्षी दलों के साथ-साथ आम नागरिक भी यह कहने लगे हैं। युद्ध की विभीषिका के बीच जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर वहां पर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है उसको लेकर भी सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आइकिया 2027-28 तक मुनाफे में आने की तैयारी में

अगले 4-5 वर्षों में 25 नए स्टोर खोलेगी

नई दिल्ली । स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर आइकिया इंडिया भारत में अपने संचालन का विस्तार कर रहा है और वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक मुनाफे में आने का लक्ष्य रखता है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुल राजस्व बढ़ाना, अधिक स्टोर खोलना, स्थाई लागत कम करना और परिचालन दक्षता में सुधार करना मुख्य रणनीति है। आइकिया अगले चार-पांच वर्षों में 25 नए छोटे और मध्यम आकार के स्टोर खोलने की योजना बना रही है। छोटे शहरों में विस्तार के लिए कंपनी छोटे आकार के स्टोर मॉडल को अपनाएगी। पहला 'सिटी स्टोर' 12 मार्च को पुणे में 32,000 वर्ग फुट में खोला जा रहा है। यह कदम कंपनी के ग्राहकों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। इसके साथ ही स्टोर अनुभव को बेहतर बनाने और ग्राहकों के लिए उपयुक्त समाधान तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अे धिकारी के अनुसार भारत कंपनी के शीर्ष तीन प्राथमिकता वाले देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में आइकिया इंडिया का कुल घाटा 1,299.4 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जबकि परिचालन राजस्व 3.33 फीसदी घटकर 1,749.50 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कंपनी का मानना है कि नए स्टोर, बेहतर संचालन और लागत नियंत्रण के माध्यम से यह स्थिति जल्द ही सुधारी जा सकती है।

जिंक में हल्की तेजी, कारोबारियों ने अपनाई सतर्क रणनीति

नई दिल्ली । मजबूत मांग के बीच शुक्रवार को जिंक की कीमत 45 पैसे बढ़कर 324.95 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। अप्रैल डिलीवरी के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में जिंक अनुबंध में 50 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया। व्यापारियों ने बताया कि जिंक में यह मामूली वृद्धि नीचे स्तर पर सीमित खरीदारी के कारण हुई। हालांकि, कोई नया संकेत या बड़ी खबर नहीं मिलने से बाजार में सतर्कता बनी रही। हालांकि कीमत में हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन व्यापारी और निवेशक बड़े बदलाव से बचते हुए प्रतीक्षित संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। यह बाजार रुझान दर्शाता है कि फिलहाल जिंक में स्थिर लेकिन सतर्क निवेश का माहौल बना हुआ है।

आरबीआई ने सीएमआई फाइनेंस पर कड़ा नियम लागू किया, निजी बैंकों पर असर

- अब ब्रोकरों को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए बैंक फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराया जाएगा

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग वित्त से कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज (सीएमआईएस) के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब ब्रोकरों को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए बैंक फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा, बैंक द्वारा दी जाने वाली सभी ऋण सुविधाओं के लिए 100 फीसदी गिरवी जरूरी होगी। पूंजी गिरवी पर कटौती को 25 फीसदी से बढ़ाकर कम से कम 40 फीसदी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 100 रुपये की गिरवी पर बैंक अब केवल 60 रुपये ही उधार दे सकता है। नए नियमों से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग महंगी और पूंजी-सघन हो जाएगी। बैंक फंडिंग पर रोक से ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध लिवरेज कम हो जाएगा, जो डेरिवेटिव और इक्विटी वॉल्यूम के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। निजी बैंकों की इस खंड में अधिक भागीदारी होने के कारण उन्हें सबसे ज्यादा असर होने की संभावना है। पहले बैंक बैंक गारंटी जारी करके शुल्क आय कमाते थे। अब नियमों के कारण बीजी की संख्या कम हो सकती है, जिससे बैंक की शुल्क आय प्रभावित होगी। एसोसिएशन ऑफ एनएसई मेंबर्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक्सचेंजों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये के बीजी हैं, और पिछले दो दशकों में गैर-निष्पादित आस्तियां लगभग शून्य रही हैं। आरबीआई ने यह कदम प्रणालीगत जोखिम को कम करने और बैंक खातों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया है। नए नियमों के लागू होने से बैंक और ब्रोकर दोनों को अधिक सतर्क रहना होगा।

ईरान-इज़राइल युद्ध से भारत में रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में आने लगी तेजी

- बासमती चावल निर्यात पर भी युद्ध का असर

नई दिल्ली ।

ईरान-इज़राइल युद्ध के बीच भारत में रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में तेजी आने लगी है। कच्चे तेल के सह-उत्पाद प्लास्टिक दाने की कीमतों में केवल दो दिनों में 12 फीसदी की वृद्धि हुई है। चूंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग और घरेलू सामान में व्यापक रूप से होता है, इसका असर रोजमर्रा के उत्पादों पर पड़ेगा। साथ ही, खाद्य तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। निर्यातकों के लिए समुद्र पार माल भेजना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कंटेनर कंपनियों ने वार सरचार्ज के तहत किरायों में 150 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। 20 टन का कंटेनर पहले 1100 डॉलर में उपलब्ध था, अब यह 3500-3700 डॉलर तक पहुंच गया है। कई कंपनियां समुद्र में फंसे माल को वापस बुला रही हैं, जिससे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। बासमती चावल निर्यात पर भी युद्ध का असर दिख रहा है। करीब 1.5 लाख टन

चावल रास्ते में फंसा है। अगर इसे वापस बुलाया गया तो भारी आर्थिक नुकसान होगा। यूरोप और अमेरिका तक माल पहुंचाने के लिए अब लंबा केप ऑफ गुड होप मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिससे 15 दिन अधिक समय और 30-40 फीसदी अतिरिक्त खर्च आएगा। भारत दवा निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कच्चा माल आयात करता है। युद्ध लंबा खिंचने पर दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें बढ़ने की संभावना है।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

भारतीय डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ ही 91.85 पर बंद हुआ। गत दिवस रुपया 91.62 पर बंद हुआ था। आज सुबह शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे मजबूत होकर 91.62 के स्तर पर था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारतीय रिफाइनरी को रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा 30 दिनों की छूट देने से रुपये को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा में गिरावट के बावजूद, घरेलू शेयर बाजारों के नकारात्मक रुख और विदेशी कोषों की निकासी ने रुपये की बढ़त को सीमित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अपने पिछले बंद भाव 91.64 पर खुला और डॉलर के मुकाबले दो पैसे की बढ़त के साथ 91.62 पर पहुंच गया। पिछले दो सत्रों में 97 पैसे की गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय रुपया 41 पैसे सुधरकर 91.64 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.37 फीसदी गिरकर 98.94 पर था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.05 फीसदी गिरकर 84.51 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

नीरव मोदी के भाइयों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का नोटिस

- नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की याचिका पर जारी किया गया

मुंबई।

मुंबई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े मामले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाइयों नीशल मोदी और नेहल मोदी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्यों न घोषित किया जाए। यह नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जारी किया गया। दोनों भाइयों को 7 मई तक जवाब देने को कहा गया है। नीरव मोदी की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी आदित्य नानावटी और संदीप मिस्त्री को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया है। अदालत का उद्देश्य है कि यदि किसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त या कुर्क की जा सके। ईडी के अनुसार नेहल मोदी ने फर्जी कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के जरिए बड़ी रकम छिपाने में नीरव मोदी की मदद की थी। वहीं नीशल मोदी दुबई में बनाई गई फर्जी कंपनियों में डमी साझेदारों की नियुक्ति और कुछ कंपनियों में हस्ताक्षरकर्ता या लाभार्थी होने का आरोप झेल रहे हैं। नेहल मोदी को 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार नेहल और नीशल दोनों बेल्जियम के नागरिक हैं। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी से 23,780 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी वर्तमान में लंदन की जेल में हैं, जबकि मेहुल चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 1,097, निफ्टी 315 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट खाड़ी में जारी संघर्ष को देखते हुए दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,097 अंक टूटकर 78,918.90 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 315.45 अंक नीचे आकर 24,450.45 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट रही। निफ्टी बैंक 2.15 फीसदी नीचे आकर 57,783.25 पर बंद हुआ। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी 2.09 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.01 फीसदी, निफ्टी सर्विसेज 1.81 फीसदी, निफ्टी ऑटो 1.06 फीसदीगिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस 2.77 फीसदी, निफ्टी एनर्जी 0.13 फीसदी, निफ्टी पीएसई 0.12 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुआ।

आज लार्जकैप की जगह पर मिडकैप और स्मॉलकैप में कम बिकवाली रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.69 प्रतिशत या 399.20 अंक की कमजोरी के साथ 57,393.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 39.90 अंक की गिरावट के साथ 16,498.90 पर था। वहीं सेंसेक्स पैक में बीईएल, सनफार्मा, एनटीपीसी, इन्फोसिस और एचसीएल टेक लाभ में रही जबकि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट,एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, इंडिगो, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और एचयूएल के शेयर गिरे।

जानकारों के अनुसार बाजार में आई गिरावट का कारण मध्यपूर्व में जारी संघर्ष है। इससे निवेशकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली भी जारी है। एफआईआई ने गुरुवार को 3,752.52 करोड़ रुपए के इक्विटी की बिकवाली की थी। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार हल्की गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स सुबह गिरावट के साथ 79,658 अंक पर खुला। इसी तरह निफ्टी भी कमजोरी के साथ 24,656 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी पर भी दबाव बना रहा।

मध्य पूर्व तनाव के बीच क्रिप्टो बाजार में उतार-चढ़ाव

- वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार का कुल मूल्य 2.40 ट्रिलियन डॉलर पर

मुंबई ।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान-इज़राइल-संयुक्त राज्य संघर्ष के असर से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह तक वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार का कुल मूल्य 2.40 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 2.46 ट्रिलियन डॉलर था। 24 घंटे में लगभग 2.46 फीसदी की गिरावट से कुल बाजार मूल्य में 0.06 ट्रिलियन डॉलर (5.50 लाख करोड़ रुपए) की कमी हुई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में 3 फीसदी से अधिक की गिरावट आई और यह लगभग 70,500 डॉलर पर कारोबार कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम भी लगभग 3 फीसदी फिसल गई। इसके अलावा बीएनबी, एक्सआरपी और सोलाना में क्रमशः 1.5, 2 और 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। जहां बड़ी क्रिप्टोकरेंसी दबाव में हैं, वहीं पाई नेटवर्क में 24 घंटे में 8 फीसदी से अधिक की तेजी आई और यह 0.1985 डॉलर तक पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते में यह मुद्रा 17 फीसदी से अधिक बढ़ चुकी है। निवेशक इसे भविष्य की संभावित बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉन और बिटगेट टोकन में भी मामूली बढ़त देखी गई। भू-राजनीतिक तनाव और बड़ी

क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट के बीच निवेशक सतर्क हैं। बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और जोखिम प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। छोटे टोकन में बढ़त के बावजूद कुल मिलाकर निवेशक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं।

कच्चा तेल 28 रुपए गिरकर 7,189 प्रति बैरल

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को भारत में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में अप्रैल डिलीवरी के लिए कच्चा तेल वायदा 28 रुपये की गिरावट के साथ 7,189 प्रति बैरल पर बंद हुआ। इस दौरान कुल 1,514 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि हाजिर बाजार में कमजोर मांग और प्रतिभागियों द्वारा बिकवाली करने के कारण कीमतों में यह कमी आई। निवेशक लाभ लेने और सुरक्षित निवेश की ओर रुझान दिखा रहे हैं, जिससे वायदा बाजार पर दबाव बना। वैश्विक स्तर पर भी तेल की कीमतें गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं। न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 1.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79.93 डॉलर प्रति बैरल पर था, जबकि ब्रेंट क्रूड 1.12 प्रतिशत गिरकर 84.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में चीनी कंपनी जियोगी की पेश की गयी कार को देखते हुए लोग।

क्यूबीई इंश्योरेंस ने भारतीय कंपनी में 100 फीसदी स्वामित्व हासिल करने की योजना बनाई

नियामक मंजूरी मिलने के बाद क्यूबीई कंपनी का एकमात्र मालिक बन जाएगा

नई दिल्ली ।

ऑस्ट्रेलिया की क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप अपने भारतीय साझेदार प्रिज्म जोनसन लिमिटेड से रहेजा क्यूबीआई जनरल इंश्योरेंस में बची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी 324 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए तैयार है। नियामक मंजूरी मिलने के बाद क्यूबीई कंपनी का एकमात्र मालिक बन जाएगा। यह बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा पूर्ण एफडीआई की अनुमति देने के बाद पहला ऐसा मामला होगा जब कोई विदेशी बीमा कंपनी भारतीय बीमा कंपनी पर 100 फीसदी स्वामित्व करेगी। रहेजा क्यूबीई, क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप और राजन रहेजा ग्रुप की कंपनी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इसमें प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में प्रिज्म जॉनसन ने कहा, 'कंपनी की अहम गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी में शेयरधारिता की बिक्री के लिए 324 करोड़ रुपये राशि तय की गई है।' कंपनी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित लेनदेन में कंपनी द्वारा प्राप्त कुल भुगतान कुछ समायोजन पर निर्भर करेगा। यह शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के मुताबिक होगा। एसपीए लागू होने से 9 महीने के भीतर प्रस्तावित लेनदेन पूरा होने का अनुमान है, जिसे 2 मार्च, 2026 को किया गया था। प्रिज्म जॉनसन ने कहा, 'प्रस्तावित लेनदेन के बाद भारत में जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय में ऑस्ट्रेलिया के क्यूबीई ग्रुप और मौजूदा शेयरधारक समझौते के साथ कंपनी का संयुक्त उपक्रम समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित लेनदेन पूरा होने पर आरक्यूबीई कंपनी की सहायक इकाई नहीं रहेगी।' कंपनी को दिसंबर 2008 में बीमा लाइसेंस मिला था। इसमें प्रिज्म जॉनसन की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और क्यूईबी की हिस्सेदारी शेष 26 प्रतिशत थी। बहरहाल एफडीआई की सीमा में बदलाव के बाद अंतरराष्ट्रीय बीमाकर्ता ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी थी, जिसके लिए उसने 2015 में 111 करोड़ रुपये निवेश किया। उसके बाद जुलाई 2020 में पेटीएम ने रहेजा क्यूईबी जनरल में 290 करोड़ रुपये में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। बहरहाल दोनों पक्ष इस समझौते को समय से पूरा नहीं कर पाए और यह सौदा समाप्त हो गया था।

अमेरिका से व्यापार करार में एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से कम शुल्क दर पर भारत का जोर

- अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखना जरूरी

नई दिल्ली । भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में शुल्क के मामले में बेहतर स्थिति मिलती रहे। भारत का मानना है कि अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को मजबूत करने के लिए यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार, पहले की बातचीत में भारत अमेरिकी प्रशासन को भारतीय उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम शुल्क रखने के लिए राजी करने में सफल रहा था। उस समय भारत के उत्पादों पर लगभग 18 प्रतिशत शुल्क तय हुआ था, जबकि इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत और चीन पर 34 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा रहा था। इस व्यवस्था से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अन्य एशियाई देशों की तुलना में अधिक अवसर मिलने की संभावना बनी थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि भारत की कोशिश यही रहेगी कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देते समय यह लाभ बरकरार रखा जाए। उनके अनुसार, समझौता इसी उद्देश्य से तैयार किया गया था कि भारत को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अधिक फायदा मिल सके। हालांकि, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद टैरिफ व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। इसी कारण भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार दर्पण जैन के नेतृत्व में प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल की 22 फरवरी की अमेरिका यात्रा स्थगित करनी पड़ी।

इस बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने हाल ही में निजी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वार्ता को सार्थक बताया। गोयल ने कहा कि भारत अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद की परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और बेहतर संभावनाओं के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी रखेगा।

भारत में महिला श्रम भागीदारी में सुधार लेकिन चुनौतियां बरकरार

- महिलाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा और औपचारिक रोजगार के अवसर सीमित

नई दिल्ली ।

पूरी दुनिया 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, लेकिन भारत में महिला श्रम बल की स्थिति अभी भी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमज़ोर है। वर्ष 2024 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर केवल 32 प्रतिशत रही, जबकि वियतनाम में यह 69 प्रतिशत, थाईलैंड में 60 प्रतिशत और चीन में 59 प्रतिशत दर्ज की गई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी है, जो स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता को दर्शाता है। कामकाजी महिलाओं में अधिकांश असुरक्षित रोजगार में हैं। भारत में श्रमबल में काम करने वाली लगभग 78 प्रतिशत महिलाएं असुरक्षित रोजगार में हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 69 प्रतिशत है। यह चीन (33 फीसदी) और ब्राजील (22 फीसदी) की तुलना में बहुत अधिक है। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा और औपचारिक रोजगार के अवसर सीमित हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियों और असुरक्षित रोजगार के कारण प्रभावित होती है। घर और परिवार की जिम्मेदारियां, साथ ही सुरक्षित और स्थायी नौकरी की कमी, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय होने से रोकती हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के

लिए नीति बदलाव जरूरी हैं। इसमें सुरक्षित और औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल और वृद्ध देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करना, और लैंगिक समानता के साथ प्रशिक्षण और करियर विकास की योजनाएँ शामिल हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अक्षर पटेल भारत के महानतम खिलाड़ियों में शामिल होने की राह पर: गावस्कर

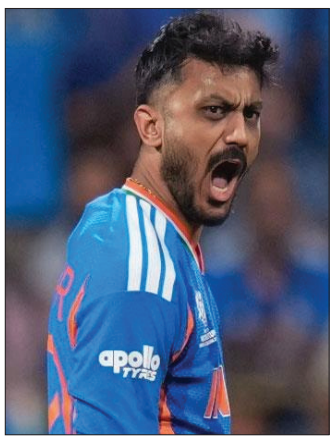

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि अक्षर पटेल क्रिकेट के हर विभाग में अपने शानदार कौशल और क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखने के कारण भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक बनने की राह पर हैं जिसकी एक बानगी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में देखने को मिली जिसमें उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से प्रभावित किया।

अक्षर पटेल ने खेल के दो अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण चरणों में खतरनाक हैरी ब्रूक और विल जैक्स को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्षर ने कवर पोजीशन से 24 मीटर पीछे दौड़कर शानदार कैच लेकर ब्रूक को पवेलियन भेजा। इसके बाद अर्शदीप सिंह की वाइड फुल टॉस गेंद को जैक्स ने डीप पॉइंट की ओर खेला। अक्षर ने अपनी बाईं ओर दौड़कर गेंद को लपका लेकिन सीमा रेखा पर संतुलन नहीं बना पाने के कारण उन्होंने उसे शिवम दुबे की तरफ उछाल दिया।

गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'अक्षर ने ब्रूक का जो कैच लिया वह अविश्वसनीय था। ब्रूक मैच का रुख बदल सकते हैं और उनका विकेट हासिल करने का हर मौका भुनाना चाहिए। अक्षर ने वही किया। वह 24 मीटर दौड़े, गेंद पर नजर रखी, खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और कैच लपक लिया। अविश्वसनीय।' उन्होंने कहा, 'विल जैक्स को आउट करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। (जैकब) बेथेल और जैक्स की साझेदारी मैच को इंग्लैंड के पक्ष में कर रही थी। लेकिन अक्षर अपनी बाईं ओर दौड़े, गेंद पकड़ी और चतुराई दिखाकर उसे शिवम दुबे के पास पहुंचा दिया। इससे उनकी क्रिकेट की समझ और अच्छी सूझबूझ का पता चलता है।'

गावस्कर ने कहा, 'शीर्ष स्तर पर आपकी सूझबूझ और जज्बा ही महान खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों से अलग करता है। अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर अक्षर भारत के महान खिलाड़ियों में से एक बनने जा रहे हैं।' गावस्कर ने कहा कि रवींद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अक्षर ने उनकी जगह को अच्छी तरह से भर दिया है।

इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, 'उनसे पहले हमारे पास रवींद्र जडेजा थे और अक्षर उनकी कमी को बखूबी पूरा कर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी में थोड़ा और निखार की जरूरत है। अनुभव के साथ यह आ जाएगा। उनकी लाइन, लेंथ और गति में निरंतर सुधार हो रहा है।' गावस्कर ने इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, 'जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज सदियों में एक बार पैदा होते हैं। वह सभी प्रारूप में खेलते हैं। इसलिए चाहे टेस्ट मैच हो या वनडे या फिर टी20 आप उन्हें गेंद दे दीजिए और वह अपना काम बखूबी निभाएंगे।'

लियोनेल मेस्सी ने डोनाल्ड ट्रंप को भेंट की रत्नों से जड़ी गुलाबी फुटबॉल

वाशिंगटन (एजेंसी)। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने पिछले साल मेजर लीग सॉकर (MLS) कप जीतने पर इंटर मियामी को सम्मानित करने के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रत्नजड़ित गुलाबी फुटबॉल भेंट की।

इंटर मियामी ने दिसंबर में वैंकूवर व्हाइटकैप्स को हराकर मेजर लीग सॉकर का खिताब जीता था। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेस्सी को लगातार दूसरे सत्र में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) चुना गया था। ट्रंप ने कहा, 'लियो (मेस्सी) आप टीम से जुड़े और आपकी टीम ने जीत हासिल की। आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं था। सच कहूं तो आप पर जितना दबाव था, उतना किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि आप जीत दिलाने में सफल रहेंगे और आपने ऐसा किया।'

मेस्सी ने ट्रंप के साथ समारोह में प्रवेश किया। वर्ष 2023 में मियामी से जुड़ने वाले मेस्सी ने कार्यक्रम के दौरान भाषण नहीं दिया। ट्रंप ने मेस्सी को संबोधित करते हुए कहा, 'आप दुनिया में कहीं भी जा सकते थे। आप दुनिया की कोई भी टीम चुन सकते थे, लेकिन आपने मियामी को चुना। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हम सभी को इस सफर में शामिल किया। आप प्रतिभाशाली और एक बेहतरीन इंसान हैं।'

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना और निकहत से रहेंगी पदकों की उम्मीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मंगोलिया में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन रही निकहत ज़रीन करेंगी। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने कड़ी चयन प्रणाली के आधार पर इस चैम्पियनशिप के लिए अपनी टीम का चयन किया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए चयनित किये गये संभावित खिलाड़ियों को पटियाला में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में शामिल किया गया था। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले मुक्केबाजों को राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में अवसर मिलेगा। इस कारण इस चैंपियनशिप का महत्व और बढ़ गया है। लवलीना को 75 किग्रा वर्ग में महिला टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। स्पेन में स्वर्ण जीतने वाली प्रीति 54 किग्रा, अरुंधति चौधरी 70 किग्रा और प्रिया 60 किग्रा को भी शामिल किया गया है। विश्व चैंपियन मीनाक्षी 48 किग्रा और जैस्मीन 57 किग्रा भी टीम का हिस्सा हैं। महिला वर्ग में निकहत ज़रीन 51 किग्रा में अगुवाई करेंगी। उनके साथ अंकुशिता बोरो 65 किग्रा, पूजा रानी 80 किग्रा, अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान 80 किग्रा रहेंगी। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी।

टी20 फ्रेंचाइजी खरीदेंगे द्रविड़ और अश्विन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

लंदन (एजेंसी)। दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और रविचंद्रन अश्विन उस भारतीय समूह का हिस्सा हैं जो यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में एक फ्रेंचाइजी खरीदने जा रहा है। बीबीसी स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में होने वाले छह टीमों के टूर्नामेंट में ग्लासगो स्थित फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए इस समूह ने एक समझौते पर सहमति जताई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईटीपीएल नीदरलैंड के रॉटरडैम स्थित अपनी फ्रेंचाइजी को भी दक्षिण अफ्रीका के निवेशकों के एक समूह को बेचने की तैयारी में है। इस समूह में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी, हेनरिक क्लासेन और जोंटी रोड्स भी शामिल हैं। संभावना है कि इस महीने के आखिर में एक कार्यक्रम में दोनों फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एम्स्टर्डम, बेलफास्ट और एडिनबर्ग में स्थित ईटीपीएल फ्रेंचाइजी को जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवेशकों को बेच दिया गया था।

अभी यह पता नहीं चल पाया है कि अश्विन ईटीपीएल में खेलेंगे या नहीं। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया था। अब वह वैश्विक फ्रेंचाइजी लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'अश्विन की भागीदारी बेहद दिलचस्प है। इससे उनके ईटीपीएल में खेलने की संभावना बन गई है, जो आयोजकों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।'

अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट, 116 वनडे और 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और कुल 765 विकेट लिए। द्रविड़ पूर्व में स्कॉटलैंड की क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और माना जा रहा है कि यही कारण है कि उन्होंने ग्लासगो स्थित फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने का फैसला किया।

स्कॉटलैंड जब इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भाग लेता था तब द्रविड़ 2003 में उसके लिए खेले थे। भारत के दिग्गज बल्लेबाज द्रविड़ ने नेशनल क्रिकेट लीग में 11 मैच खेले, जिसमें उन्होंने तीन शतकों सहित 600 रन बनाए। द्रविड़ ने भारत के लिए 164 टेस्ट और 344 वनडे मैच खेले। उन्होंने इनमें 48 शतकों सहित 24,000 से अधिक रन बनाए। वह नवंबर 2021 से जून 2024 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी रहे।

डायने पैरी ने वीनस विलियम्स को किया इंडियन वेल्स से बाहर

इंडियन वेल्स (कैलिफोर्निया)। फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी डायने पैरी ने सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को पहले दौर के मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। फ्रांस की डायने पैरी ने गुरुवार को दो घंटे 21 मिनट तक चले मुकाबले में अमेरिका की वीनस को 3-6, 6-7 (4), 1-6 से हराया। इसी के साथ वीनस का बीएनपी परिबास ओपन 2026 में अभियान समाप्त हो गया। बीएनपी परिबास ओपन को इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। वीनस विलियम्स ने इंडियन वेल्स में पदार्पण के 30 साल बाद की वापसी थी। उन्होंने पहली बार 1996 में 15 वर्ष की उम्र में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उन्हें इस टूर्नामेंट के एकल और युगल ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड दिया गया था।

टी20 विश्व कप : संजू सैमसन की हालिया इनिंग्स पर बोले रवि शास्त्री, इसी बदलाव की वजह से आए परिणाम

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि बल्लेबाजी करते समय संजू सैमसन मानसिक रूप से अधिक मजबूत हैं और टी-20 विश्वकप में उनके हालिया परिणाम इसी बदलाव की वजह से आए हैं।

शास्त्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि आखिरकार उन्हें यह एहसास हो गया है और वे इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें और अधिक एकाग्र होने की आवश्यकता है। उन्हें अपने शॉट चयन में अधिक समझदारी दिखानी होगी और अपनी ताकत पर ध्यान देना होगा।संजू के साथ बात यह है कि उनके पास हर शॉट आता है, लेकिन एकाग्रता में कमी रह जाती है। मुझे लगता है कि वह मानसिक रूप मजबूत हो गया है और जब से वह टीम में आया है, तब से किसी को भी उसके कौशल या प्रतिभा पर शक नहीं हुआ है।'

शास्त्री ने कहा है कि उसका सर्वश्रेष्ठ फॉर्म अभी बाकी है क्योंकि भारतीय टीम में उसकी भूमिका अब साफ तौर पर तय है। उन्होंने कहा, 'वह अभी भी सिर्फ 31 साल का है और एक असली मैच-विनर है। और जब आप (आज) जैसे शॉट खेलते हुए देखते हैं, तो उसमें क्लास, टच, पावर और जबरदस्त फोर्स दिखती है। यह बस अविश्वसनीय है।' हालांकि सैमसन का फॉर्म भारत के लिए एक सुखद सरप्राइज रहा है, लेकिन साथी ओपनर अभिषेक शर्मा की हालिया कोशिशें न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले टी-20 विश्वकप के फाइनल से पहले कुछ चिंता का विषय हैं।

आईपीएल की तैयारियों के लिए 15 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी आरसीबी : प्रसाद

मुम्बई। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) आईपीलएल की तैयारियों के लिए 15 मार्च को अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगी। अभी राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) इस स्टेडियम में सभी तैयारियों को पूरा करने के इंतजाम कर रहा है। केएससीए के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद को उम्मीद है कि 15 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम के एकत्रित होने से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सभी जरुरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। आरसीबी ने इससे पहले कहा था कि वह आईपीए 2026 के शुरुआती मैच सहित पांच लीग मैच इस स्टेडियम में खेलेगी जिसके साथ ही घरेलू मैदानों को लेकर जारी संदेश दूर हो गया था। प्रसाद ने कहा, ''हां, अब भी स्टेडियम में कुछ काम बचा हैं और जहां तक हमारा सवाल है यह तय समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा जो हमने महेश्वर राव की अध्यक्षता वाली (राज्य द्वारा नियुक्त) विशेषज्ञ समिति को दी है।'' उन्होंने कहा, ''हमने उन्हें जितना हो सका उतना संतुष्ट कर दिया है।गौरतलब है कि पिछले साल आरसीबी के आईपीएल खिताब जीतने के बाद हुए समारोह में हुड़दंग मचने के बाद से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इस कारण इसमें मैचों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गयी थी जो अब हटा दी गयी है।

टी20 विश्व कप : चक्रवर्ती की फॉर्म भारत के लिए चिंता, साथी क्रिकेटर बोला- वह अब भी तुरुप का इक्का

मुंबई (एजेंसी)। पिछले कुछ मैचों में वरुण चक्रवर्ती के खराब प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी का रहस्य अब सुलझता नजर आ रहा है लेकिन उनके साथी खिलाड़ी अब भी इस लेग स्पिनर को अपनी टीम का तुरुप का इक्का मानते हैं। अगर टीम प्रबंधन रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में दुनिया के शीर्ष गेंदबाज को टीम में बनाए रखने का फैसला करता है, तो वह भारत के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। टूर्नामेंट के सुपर आठ चरण के बाद से उनकी फॉर्म में लगातार गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

चक्रवर्ती को टूर्नामेंट के अंतिम चरण में खराब प्रदर्शन करने के बाद अपने मन में मौजूद शंकाओं को दूर करने की जरूरत होगी। इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में जैकब बेथेल ने चक्रवर्ती को अपने निशाने पर रखा था। इस भारतीय गेंदबाज ने चार ओवर में 64 रन देकर एक विकेट लिया। भारत के उप कप्तान अक्षर पटेल ने हाल ही में चक्रवर्ती से बातचीत की है और इस बात पर जोर दिया कि जब चीजें अनुकूल नहीं चल रही हों तब भी अपनी रणनीति पर कायम रहना कितना महत्वपूर्ण है।

अक्षर ने कहा, 'हमने चक्रवर्ती की मौजूदा समस्याओं के बारे में बात की है। हमने इस समय कई नॉकआउट मैच खेले हैं, इसलिए सही मानसिकता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल और बाकी चीजें भी मायने रखती हैं, लेकिन हमने उससे यही कहा कि जब उसकी गेंदों पर रन बनने लगें तो अपनी रणनीति को नहीं बदलें।'

उन्होंने कहा, 'पहले आपकी रणनीति विकेट को निशाना बनाकर गेंदबाजी करने की होती है और फिर अचानक आप लाइन बदल देते हैं। दबाव वाली परिस्थितियों में गलतियां हो सकती हैं। हम उसे लगातार यही कहते रहते हैं कि तुम टीम के लिए तुरुप का इक्का हो। खुद पर भरोसा रखो और पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करो।'

वरुण ने सेमीफाइनल से पहले नेट पर जमकर अभ्यास किया, लेकिन पावरप्ले में गेंदबाजी करने के बाद वह अपनी लय हासिल नहीं कर पाए। इंग्लैंड ने चक्रवर्ती के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और बाएं हाथ के बल्लेबाज बेथेल ने उन्हें किसी भी समय लय हासिल नहीं करने दी। उन्होंने चक्रवर्ती के पहले ही ओवर में तीन छक्के जड़े। बेथेल ने चक्रवर्ती की 13 गेंदों में 42 रन बनाए। चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से बहुत शॉर्ट या फिर ओवर पिच गेंदबाजी कर रहे हैं जिससे बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंदों को समझना आसान हो गया है।

अक्षर ने कहा, 'अगर आप देखें तो कुछ छक्के खाने के बाद भी उसने जोस बटलर का विकेट लिया। वह नंबर एक टी20 गेंदबाज है और वह जानता है कि उसे क्या करना है। यह मानसिकता की बात है। हमें अभी एक और मैच खेलना है और उम्मीद है कि वह फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।'

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि चक्रवर्ती को अपनी गति कम

करनी होगी। हरभजन ने कहा, 'वह मैच विजेता गेंदबाज है लेकिन शुरुआत से ही निशाना बनाए जाने पर कोई भी गेंदबाज दबाव में आ जाता है। तेज गति के अलावा वह सही लेंथ से गेंदबाजी नहीं कर पा रहा है। विकेट को निशाना बनाकर गेंदबाजी करना उसका मजबूत पक्ष है लेकिन कई बार उसने अपनी इस रणनीति से हटकर वाइड गेंदें फेंकी हैं। वह दबाव में हैं। उसे बस इतना करना है कि वह नेट पर जमकर अभ्यास करे।'

एशियन कप में जापान से भिड़ेगी भारतीय महिला फुटबॉल टीम

पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)। भारतीय सीनियर महिला नेशनल टीम शनिवार को रेकटेंगुलर स्टेडियम में एएफसी महिला एशियन कप ऑस्ट्रेलिया 2026 के अपने दूसरे ग्रुप सी मुकाबले में मजबूत जापान से भिड़ेगी। फीफा महिला वर्ल्ड रैंकिंग में आठवें स्थान पर काबिज जापान को ब्लू टाइग्रेसेस (67वें स्थान पर) पर साफ बढ़त मिली है, क्योंकि उसने पिछले तीनों मैच जीते हैं। नादेशिको ने इन तीन मैचों में 19 बार गोल किए हैं। वहीं अपने पहले मैच में वियतनाम से 1-2 से हारने के बावजूद भारत अभी ग्रुप में तीसरे स्थान पर है। भारत को वियतनाम के खिलाफ मैच में मिली हार से उबरने के लिए दो दिन मिले हैं और जापान के खिलाफ मुकाबले के लिए अपने खिलाड़ियों को अच्छी हालत में वापस लाना मुख्य कोच अमेलिया वाल्वर्डे की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है। वाल्वर्डे ने कहा, 'हम जानते हैं कि जापान एक ऐसी टीम है जो बहुत जोश के साथ पजेशन रखना पसंद करती है। उन्हें गेम पर हावी होना पसंद है, लेकिन हमें अपना गेम स्वयं तैयार करना होगा। हमें उम्मीद है कि हम शानदार प्रदर्शन करेंगे, फिर से बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, जैसा हम पिछले बुधवार को थे। हम गेम के पहले मिनट से ही कोशिश करेंगे। हमें अपनी एनर्जी अपनी टीम पर फोकस करने की आवश्यकता है।'

'भारत खुशकिस्मत है कि बुमराह जैसा गेंदबाज हमारे पास है': पूर्व ऑलराउंडर

मुम्बई (एजेंसी)। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की रोमांचक जीत के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी चर्चा का केंद्र बन गई है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बेहद खुशकिस्मत है कि ऐसा गेंदबाज टीम के लिए खेलता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बुमराह की डेथ ओवर गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया। पठान का मानना है कि बुमराह जैसे गेंदबाज पीढ़ियों में एक बार ही देखने को मिलते हैं।

इरफान पठान ने बुमराह की जमकर की तारीफ

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह भारत को मिला एक बेहद खास गेंदबाज है। उनके अनुसार क्रिकेट इतिहास में बहुत कम गेंदबाज ऐसे हुए हैं जिनके पास इतनी विविधता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता हो। पठान ने कहा कि बुमराह के पास यॉर्कर, स्लोअर बॉल, इनस्विंग, आउटस्विंग और बाउंसर जैसी हर तरह की गेंद है, जिससे वह किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। उनका मानना है कि भारत को पहले कभी बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं मिला और दुनिया में भी इस तरह के गेंदबाज बेहद कम देखने को मिलते हैं।

देश ओवर में बुमराह ने बदला मैच का रुख

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन की 89 रन की शानदार पारी शामिल थी। जवाब में इंग्लैंड ने दमदार बल्लेबाजी की और मैच आखिरी ओवरों तक रोमांचक बना रहा। लेकिन मुकाबले का सबसे अहम मोड़ तब आया जब जसप्रीत बुमराह ने 18वां ओवर फेंका।उस समय इंग्लैंड को आखिरी तीन ओवरों में 45 रन की जरूरत थी, लेकिन बुमराह ने अपने ओवर में सिर्फ छह रन दिए और चार सटीक यॉर्कर डाले। इस शानदार ओवर ने इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया।

हार्दिक पांड्या ने बढ़ाया दबाव

बुमराह के शानदार ओवर के बाद हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ नौ रन दिए और खतरनाक बल्लेबाज सैम करन को आउट कर दिया। अंत में इंग्लैंड की टीम 246/7 तक ही पहुंच सकी और भारत ने सात रन से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बना ली।

बुमराह को मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच

इरफान पठान का मानना है कि इस मुकाबले में बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह मैच एक बेहद फ्लैट पिच पर खेला गया था, जहां लगभग 500 रन बने। पठान के मुताबिक ऐसे हालात में जहां बाकी गेंदबाज 10 या उससे ज्यादा इकॉनमी से रन दे रहे थे, वहां बुमराह ने रन पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। उनका कहना है कि कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी ही असली मैच विनर होता है।

क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस ने दिलाया अहम विकेट

पठान ने बुमराह की क्रिकेटिंग समझ की भी खास तौर पर तारीफ की। उन्होंने बताया कि जब बुमराह गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक थे। बुमराह ने तेज गेंद फेंकने की बजाय चतुराई दिखाते हुए स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रूक तेज गेंदों को पसंद करते हैं। इस रणनीति ने काम किया और ब्रूक का कैच अक्षर पटेल ने लपक लिया।

फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 1/33 का प्रभावी स्पेल डाला, जबकि अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी अहम विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया। अब भारत का सामना फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा। यह मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम एक और आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स के कार्यक्रम में बदलाव नहीं : औल्ड

मेलबर्न। खाड़ी में जारी संघर्ष के बाद भी फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन तय समय पर ही किया जाएगा। इसकी अभ्यास रेस 6 मार्च से शुरु होगी। वहीं मुख्य रेस 8 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रैविस औल्ड ने कहा है कि अधिकारियों, टीम सदस्यों और ड्राइवरों पर इस संघर्ष का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में सत्र की इस पहली रेस के कार्यक्र में बदलाव नहीं होगा। औल्ड ने माना है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के करण बड़े स्तर पर उड़ानों के रद्द होने से कुछ टीमों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी हैं। इसी को देखते हुए कि फॉर्मूला वन टीम के अधिकारी इस प्रयास में लगे हैं कि ड्राइवर और टीम के लोग वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित रुप से मेलबर्न पहुंच सकें। औल्ड ने कहा, हर कोई रेस के लिए यहां आने तैयार है, इससे प्रशंसकों को तय कार्यक्रम के अनुसार ही रेस देखने को मिलेगी जो उनके लिए भी राहत की बात है। उन्होंने कहा, कुछ ड्राइवर और कुछ टीम सदस्य पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में हैं पर ब्रिटेन और यूरोप से कई सदस्यों को आना है जिसमें रेसर भी शामिल हैं। ऐसे में इन्हें कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता देखना होगा। मुझे भरोसा है कि वे लोग भी इस बारे में विचार कर रहे होंगे। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो हजार एफ वन कर्मचारियों को पश्चिम एशिया में फंसने से बचने के लिए यूरोप से मेलबर्न के लिए अपनी उड़ानों को फिर से पुर्नप्रबंधित करना होगा। फार्मुला वन करीब 500 स्टाफर्स को तीन विशेष उड़ानो से लाने का प्रयास कर रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण; कितनी घातक?

वाशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने मंगलवार रात कैलिफोर्निया तट पर अपनी 'डूम्सडे' बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 'मिनटमैन ढ्ढढ्ढढ्ढ' नाम की यह मिसाइल बेहद घातक है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इसे सांता बारबरा के पास वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रात 11 बजे लॉन्च किया गया। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने जानकारी दी कि 'जीटी 254' नाम का यह रॉकेट बिना किसी हथियार के छोड़ा गया था। इसने प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड्स के पास अपने तय लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने बताया कि इस मिसाइल को इसकी सटीकता और ठिकानों को परखने के लिए दागा गया था। 576वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इस टेस्ट से मिसाइल सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों की कार्यक्षमता का अंदाजा लगाने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षणों से देश की परमाणु शक्ति के जमीनी हिस्से को और भी मजबूत और तैयार रखा जा सकता है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इस्राइल ने हाल ही में ईरान पर हमला किया था। उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में जंग छिड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज करने चेतावनी दी है और कहा है कि एक बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि, एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने यह भी साफ किया कि मंगलवार का यह परीक्षण रूटीन था और इसकी योजना वर्षों पहले ही बना ली गई थी।

इजराइल–ईरान जंग के बीच बंकर में शादी

तेल अवीव/तेहरान, एजेंसी। ईरान के खिलाफ अमेरिका–इजराइल हमले का आज छठा दिन है। इजराइल और अमेरिकी सेनाओं ने गुरुवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। ईरान के इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका–इजराइल तीन दिन में 2000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। इससे ईरान में 1,045 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मिशा नाम के एक शख्स ने बुधवार को इजराइल के तेल अवीव स्थित एक भूमिगत बम शेल्टर में शादी की। इस दौरान अपनी दुल्हन लियोर के चेहरे पर घूंघट डाला। यह शादी पहले पेटाह टिकवा में होने वाली थी, लेकिन जंग की वजह से इसे बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया। मिशा ने कहा- हालात कैसे भी हों नई शुरुआत होनी चाहिए। जिंदगी रुकना नहीं चाहिए। इजराइल में यहूदी पर्व पुरिम) मनाया जा रहा है। इस मौके पर तेल अवीव के एक बम शेल्टर में स्थानीय लोग एकत्रित हुए। पुरिम पर्व प्राचीन फारस में यहूदियों के नरसंहार से बचाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। यरुशलम के एक बंकर में स्थानीय लोगों ने नाचते- गाते पुरिम पर्व मनाया। यहां के लोगों का कहना है कि जंग के दौरान भी खुशी मनाना उनके अस्तित्व का प्रमाण है। यरुशलम में बुधवार को पुरिम पर्व मनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। इस दौरान इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा था।

'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने की तैयारी में पाक, ईरान युद्ध ने बिगाड़ा तेल का खेल; सऊदी की शरण में शहबाज

इस्लामाबाद, एजेंसी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इस संभावित संकट का सीधा और गहरा असर पाकिस्तान पर पड़ने की आशंका है। कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित होने के डर से पाकिस्तान सरकार अब आपातकालीन कदम उठाने की तैयारी कर रही है। ईंधन संरक्षण के इस कड़े कदम के तहत, सरकार देश में अनिवार्य रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' (ङ्खस्न ॥) लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लोगों को घर पर ही रोकना और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करना है, ताकि पेट्रोल और डीजल की भारी खपत को नियंत्रित किया जा सके। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बुधवार को सऊदी अरब से एक वैकल्पिक मार्ग के जरिए तेल आपूर्ति जारी रखने का आधिकारिक अनुरोध किया है। पाकिस्तान के संघीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल–मल्की के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, मलिक ने सऊदी अरब से लाल सागर पर स्थित यानबू बंदरगाह के जरिए तेल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सऊदी राजदूत ने पाकिस्तान को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि रियाद किसी भी आपातकालीन ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

ईरान युद्ध पर अमेरिका का बड़ा कबूलनामा; रक्षा मंत्री हेगसेथ बोले- हर मिसाइल रोक पाना संभव नहीं

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्वीकार किया है कि ईरान की ओर से दागी जाने वाली हर मिसाइल या ड्रोन को रोक पाना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना की ताकत और तकनीक इतनी मजबूत है कि ईरान के हवाई क्षेत्र पर धीरे-धीरे अमेरिका का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। पेंटागन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमला शुरू करने से पहले ही अधिकतम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि सैनिकों को नुकसान कम से कम हो।

अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा अब भी बना हुआ : अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन कैन ने भी साफ कहा कि अमेरिकी सैनिक अभी भी खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता और स्थिति को गंभीरता से देखने की जरूरत है। रविवार को कुवैत के एक नागरिक बंदरगाह क्षेत्र में ईरानी ड्रोन हमले में छह अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। यह हमला सेना के मुख्य बेस से करीब 10 मील दूर एक ऑपरेशन सेंटर पर हुआ था। बताया गया कि यह केंद्र शिपिंग कंटेनर जैसी इमारत में बना था और वहां मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अमेरिका ईरान में जमीनी सैनिक भेज सकता है, तो जनरल कैन ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि फिलहाल यह योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने मौजूद किसी विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

युद्ध 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक चल सकता है- हेगसेथ : रक्षा मंत्री हेगसेथ ने संकेत दिया कि यह संघर्ष पहले की उम्मीद से ज्यादा लंबा चल सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध तीन हफ्ते से लेकर आठ हफ्ते तक भी चल सकता है। उनके अनुसार युद्ध की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि हालात किस दिशा में बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अभी युद्ध की गति और रणनीति अमेरिका तय कर रहा है और ईरान दबाव में है। हेगसेथ ने बताया कि अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और बमवर्षक भेज रहा है, ताकि अभियान को मजबूत बनाया जा सके।

अमेरिका का दावा- हथियारों की कमी नहीं : हेगसेथ और जनरल कैन दोनों ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों और गोला-बारूद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जब ईरान के आसमान पर नियंत्रण बढ़ गया है तो पारंपरिक लेकिन सटीक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल कैन के अनुसार अमेरिकी हमलों ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से अब अमेरिकी विमान ईरान के अंदरूनी इलाकों तक जाकर हमला कर पा रहे हैं।

ईरान के हमलों में कमी, लेकिन खतरा बना हुआ : अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार युद्ध की शुरुआत की तुलना में ईरान द्वारा दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या में लगभग 86 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में भी इसमें करीब 23 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा एक-तरफा हमला करने वाले ड्रोन के इस्तेमाल में भी लगभग 73 प्रतिशत की कमी देखी गई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान संभवतः अपने कुछ हथियार भविष्य के लिए बचाकर रख रहा है ताकि युद्ध लंबा खींच सके।

पश्चिम एशिया से अमेरिकी नागरिकों की निकासी : इस बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया के 14 देशों में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी है। क्षेत्र में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण कई जगहों का हवाई क्षेत्र बंद हो गया है और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हो रही हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 6,500 अमेरिकियों को क्षेत्र से निकालने में मदद की गई है। वहीं शनिवार से अब तक 17,500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक पश्चिम एशिया से अमेरिका लौट चुके हैं, जिनमें से अधिकांश लोग व्यावसायिक उड़ानों के जरिए लौटे हैं।

टैरिफ नीति पर बुरे फंसे ट्रंप: रिफंड पर न्यूयॉर्क कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बोले- कंपनियों को लौटाया जाएगा पैसा

न्यूयॉर्क , एजेंसी। अमेरिका में टैरिफ विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने भी ट्रंप प्रशासन को झटका दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिन कंपनियों ने ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए आयात टैरिफ का भुगतान किया था, उन्हें अब पैसा वापस किया जाएगा। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जज रिचर्ड ईटन ने कहा कि सभी आयातक कंपनियां यूएस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का लाभ पाने की हकदार हैं, जिसमें पिछले महीने ट्रंप के कई टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया था। फैसला सुनाते हुए यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में न्यायाधीश रिचर्ड ईटन ने कहा कि सभी आयातक रिकॉर्ड के मालिक इस फैसले का लाभ पाने के हकदार हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया, जिसमें अमेरिकी टैरिफ को अवैध बताते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 की अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत लगाए गए टैरिफ संविधान के खिलाफ हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजर : इतना ही नहीं अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा था कि राष्ट्रपति अकेले टैरिफ तय और बदल नहीं सकते, क्योंकि कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस का है। इस फैसले में पारस्परिक टैरिफ, जो लगभग सभी देशों पर लगाए गए थे, को भी अवैध घोषित किया गया।

कंपनियों के रिफंड पर कोर्ट सख्त : न्यायाधीश ईटन ने अपने फैसले में कहा कि वह अकेले आईईईपीए टैरिफ की वापसी के मामलों को सुनेंगे। इससे यह साफ हुआ कि कंपनियों को टैरिफ लौटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र नहीं किया। इसपर वकील रयान मेजरस ने कहा कि सरकार शायद इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या वापसी की प्रक्रिया को रोकने के लिए समय मांगेगी। बता दें कि अमेरिका सरकार ने अब तक इन टैरिफ से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा किए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को कुल 175 बिलियन डॉलर तक की वापसी करनी पड़ सकती है। ऐसे में यह फैसला विशेष रूप से एटमस निस्पंदन, नाशविल, टेनेसी की कंपनी के मामले पर आया है, जिसने टैरिफ की वापसी का दावा किया था। यह कंपनी फिल्टर्स और अन्य फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बनाती है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई सामान अमेरिका में आता है, तो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन उसका अंतिम हिसाब करती है, जिसे लिक्विडेशन कहते हैं।

मध्य पूर्व में तनाव के बीच घर लौट रहे दक्षिण कोरियाई पर्यटक

सियोल , एजेंसी। मध्य पूर्व देशों में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरियाई पर्यटक धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे हैं। वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था होने के बाद उनकी वापसी आसान हो सकी है। पर्यटन उद्योग के सूत्रों के अनुसार, बुधवार तक प्रमुख ट्रैवल एजेंसियों के 400 से अधिक पर्यटक दुबई में ठहरे हुए थे। इनमें हाना टूर के करीब 150 ग्राहक, मोड टूर के लगभग 190 ग्राहक और येलो बैलून टूर के करीब 70 ग्राहक शामिल हैं। यह जानकारी योनहाप समाचार एजेंसी ने दी है। हाना टूर ने बताया कि उसके 40 ग्राहक दिन में पहले ही दुबई से रवाना हो चुके हैं और वे गुरुवार देर रात तक दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले हैं। वहीं मोड टूर ने भी अपने 39 ग्राहकों के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की है, जिनके इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचने की उम्मीद है। इन यात्रियों के लौटने के बाद भी 330 दक्षिण कोरियाई पर्यटक दुबई में ही रहेंगे। कंपनियों के मुताबिक मध्य पूर्व के अन्य देशों में मौजूद पर्यटक फिलहाल बिना किसी बड़ी समस्या के अपने देश लौट रहे हैं। हाना टूर के एक अधिकारी ने बताया कि काहिरा में मौजूद उनके समूह के पर्यटक बिना किसी व्यवधान के वापस लौट रहे हैं। वहीं, येलो बैलून टूर के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी काहिरा और जॉर्डन के अम्मान में मौजूद अपने ग्राहकों के लिए इस सप्ताह के अंत में वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। इस बीच सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य नीति निर्माता ने चेतावनी दी कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण मध्य पूर्व को होने वाला दक्षिण कोरिया का निर्यात प्रभावित हो सकता है। उससे निपटने के लिए कदम तैयार किए जा रहे हैं। नेशनल असेंबली की नीति समिति की अध्यक्ष हान जियोंग-ए ने संबंधित संसदीय समितियों के डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ बैठक में कहा कि बढ़ता संघर्ष मध्य पूर्व के प्रमुख देशों को होने वाले दक्षिण कोरिया के निर्यात पर असर डाल सकता है, जो पिछले वर्ष 200 ट्रिलियन वॉन रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मध्य पूर्व में लगभग 100 ट्रिलियन वॉन के वे प्रोजेक्ट, जिन्हें हमारी कंपनियों ने स्मार्ट सिटी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर जैसे भविष्य के विकास इंजन के रूप में विकसित किया है, देरी का शिकार हो सकते हैं।

पूर्व अमेरिकी कर्नल का बड़ा दावा- हमारे बेस तबाह, अब भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है

वाशिंगटन, एजेंसी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा, 'अमेरिकी सैनिक अभी भी खतरे में हैं, और हमें यह साफ पता होना चाहिए कि जोखिम अभी भी बहुत ज्यादा है।' अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को स्वीकार किया कि ईरान के कुछ हवाई हमले अभी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

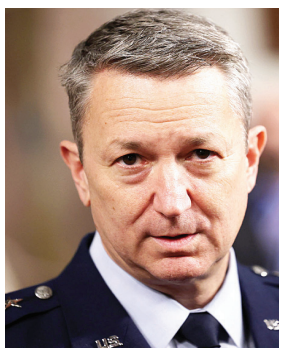

ईरान और अमेरिका में जंग जारी है। इसी बीच अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल ने दावा किया है कि ईरान मजबूती से लड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई बेस तबाह हो गए हैं और युद्ध के लिए भारत और उसके बेस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार या भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 6 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने चीन और रूस की तरफ से ईरान को मदद मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'चीन और रूस हर चीज पर नजर रखे हुए हैं और सरकार के साथ संपर्क में हैं। वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सफलता (ईरान) को मिली है। खासतौर से इजरायल और हमारे अमेरिकी बेस पर मिली है।' उन्होंने कहा, 'हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं। हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। असल में हमें भारत और भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर रहना होगा...। मुझे लगता है कि ईरान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।' ईरान के कुछ हमले टारगेट तक पहुंच सकते हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को स्वीकार किया कि ईरान के कुछ हवाई हमले अभी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की सैन्य सर्वोच्चता उसे इस्लामी गणराज्य के हवाई क्षेत्र पर तेजी से नियंत्रण करने में मदद कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास युद्ध के लिए पर्याप्त साजो सामान है। ईरान पर इजरायल के साथ हमले शुरू करने के कुछ दिन बाद, हेगसेथ ने पेंटागन में संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में 'कोई कसर' नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, 'इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन हमने यह पक्का किया कि हमला करने से पहले अधिक से अधिक रक्षा और प्रतिरक्षा तैयार किया जाए।' उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इलाके में और ड्रोन या मिसाइल हमलों से सैनिकों को नुकसान हो सकता है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने इस लड़ाई में और अमेरिकी लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है क्योंकि यह संघर्ष लंबा चल सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा, 'अमेरिकी सैनिक अभी भी खतरे में हैं, और हमें यह साफ पता होना चाहिए कि जोखिम अभी भी बहुत ज्यादा है।'

सनसनीखेज दावा: 'मेरे पास कोई चारा नहीं था', ट्रंप की हत्या क्यों करना चाहता था पाकिस्तानी आसिफ?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोपी एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने बुधवार को अदालत में जूरी के सामने गवाही दी। उसने दावा किया कि उसने ईरान के कुलीन 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' के साथ अपनी मर्जी से काम नहीं किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने आसिफ मर्चेंट पर आरोप लगाया है कि उसने ट्रंप और अन्य राजनेताओं की हत्या की योजना के तहत अमेरिका के भीतर लोगों की भर्ती करने की कोशिश की। यह साजिश अमेरिका द्वारा ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए रची गई थी। ईरान में सैन्य और आर्थिक शक्ति के साथ-साथ एक मजबूत खुफिया नेटवर्क होने के कारण 'रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' की वहां केंद्रीय भूमिका है।

आरोपी मर्चेंट का अदालत में बचाव : 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवाद और हत्या की सुपारी के आरोपों का सामना कर रहे मर्चेंट ने अदालत में कहा- मैं यह काम इतनी स्वेच्छा से नहीं करना चाहता था। उसने दावा किया कि उसने तेहरान में रह रहे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूरी में इस साजिश में हिस्सा लिया। मर्चेंट ने यह भी कहा कि उसे कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का सीधा आदेश नहीं मिला था। हालांकि, तेहरान में बातचीत के दौरान उसके ईरानी हैंडलर ने तीन प्रमुख नेताओं के नाम लिए थे- डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन (तत्कालीन राष्ट्रपति), निक्की हेली (2024 के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की पूर्व दावेदार) सरकारी वकीलों ने मर्चेंट के 'मजबूरी' वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। 2024 से चल रहे इस मामले में, मंगलवार को जज को भेजे गए एक पत्र में अभियोजकों ने कहा कि सच्चे दबाव या जबरदस्ती को साबित करने के लिए कोई भी उचित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस बीच, मर्चेंट के वकीलों और वाइट हाउस की तरफ से इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस मामले का ट्रायल पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है। गौरतलब है कि ट्रायल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही ट्रंप के आदेश पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं। इन संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और मध्य पूर्व के देश के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए। रविवार को एबीसी न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने खामेनेई को मारने वाले इस ऑपरेशन का बचाव किया।

किम जोंग उन का दावा- परमाणु ताकत से लैस होगी उत्तर कोरिया की नौसेना, नए युद्धपोत का किया निरीक्षण

सियोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने लगातार दो दिनों तक नए युद्धपोत (डिस्ट्रॉयर) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने युद्धपोत से दागी गई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी देखा। किम ने अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से और अधिक मजबूत करने का वादा किया है। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इस दौरे की जानकारी दी।

किम जोंग उन ने मंगलवार और बुधवार को नम्पो के पश्चिमी शिपयार्ड का दौरा किया। वहां उन्होंने 5,000 टन के युद्धपोत 'चो ह्योन' जैसी श्रेणी के तीसरे जहाज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। किम ने कहा कि 'चो ह्योन' का विकास उनकी सेना की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है। यह जहाज परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए बनाया गया है। दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों का मानना है कि इस जहाज को बनाने में रूस ने मदद की है। हालांकि, कुछ लोग इसकी कार्यक्षमता पर संदेह भी जता रहे हैं।

पिछले साल मई में इसी श्रेणी का दूसरा जहाज लॉन्चिंग के दौरान खराब हो गया था। इस नाकामी पर किम जोंग उन ने बहुत गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने इसे एक अपराध बताया था। उस जहाज का नाम 'कांग कोन' था, जिसे मरम्मत के बाद जून में फिर से लॉन्च किया गया। किम ने अब लक्ष्य रखा है कि अगले पांच वर्षों तक हर साल दो बड़े युद्धपोत बनाए जाएंगे। उनका पूरा ध्यान अब नौसेना की क्षमता बढ़ाने पर है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाना भी शामिल है। नम्पो शिपयार्ड में बन रहा तीसरा युद्धपोत अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

किम जोंग उन ने दावा किया कि नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की कोशिशों में अच्छी प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव समुद्री सीमाओं की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाएगा। जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया एक नई समुद्री सीमा घोषित करने की तैयारी में है। किम ने साफ कर दिया है कि वे पुरानी समुद्री सीमा (एनएलएल) को मान्यता नहीं देते हैं। इस वजह से आने वाले समय में समुद्री क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।

किम ने अपनी सेना को मजबूत करने के साथ-साथ कूटनीतिक रास्ते भी खुले रखे हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की संभावना जताई है। हालांकि, उन्होंने शर्त रखी है कि अमेरिका को परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी जिद छोड़नी होगी। किम ने स्पष्ट किया कि वे अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना जारी रखेंगे ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। उन्होंने दक्षिण कोरिया के प्रति भी अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। उत्तर कोरिया की इन गतिविधियों ने पूरे एशिया क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है।

पाकिस्तान-अफगान सीमा तनाव: छह दिन से जारी जंग के बीच तुर्किये ने की मध्यस्थता की पेशकश

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी झड़पें अब छठे दिन में पहुंच गई हैं। इसके बाद भी दोनों तरफे से हमले जारी है। इसी बीच अब इस मामले में तुर्किये की एंट्री हुई है। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच नया युद्धविराम कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। बता दें कि संघर्ष की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई, जब अफगानिस्तान ने गुरुवार को पाकिस्तान पर हमले किए। यह हमला पाकिस्तान द्वारा पिछले सप्ताहांत किए गए हवाई हमलों के जवाब में बताया गया।

इसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया और कहा कि वह अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसी स्थिति में है। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। इससे पहले दोनों देशों के बीच अक्तूबर 2024 में कतर और तुर्किये की मदद से युद्धविराम हुआ था। उस समझौते के बाद इस्तांबुल में छह दिन तक बातचीत भी हुई और नवंबर में तीसरे दौर की वार्ता पर सहमति बनी थी। लेकिन 6 और 7 नवंबर को हुई बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और शांति प्रक्रिया रुक गई।

तुर्किये का राष्ट्रपति और पाकिस्तानी पीएम की बातचीत : तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार,एर्दोगन ने फोन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की निंदा की और कहा कि तुर्किये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से युद्धविराम बहाल कराने में मदद करेगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे तौर पर इस प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की, लेकिन बताया कि दोनों नेताओं ने 2,611 किलोमीटर लंबी अफगान-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

मामले में अफगान भी मौन : दूसरी ओर अभी तक इस मामले में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से एर्दोआन की पेशकश पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि पिछले हफ्ते तुर्किये के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से सीमा पर हालात को लेकर बातचीत की थी। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति तभी संभव है जब अफगान तालिबान पाकिस्तान विरोधी उग्रवादियों से अपने संबंध खत्म करे। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

अब समझिए पूरे संघर्ष की कहानी : गौरतलब है कि सीमा पर लड़ाई मुख्य रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इलाकों में हो रही है। दोनों देश एक-दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की पहुंच सीमित होने के कारण इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले पांच दिनों में 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 28 अफगान सैनिक भी मारे गए। दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि पिछले छह दिनों में 481 अफगान सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे उग्रवादी संगठन पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। लेकिन काबुल की सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देती।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

590 करोड़ के बैंक घोटाले में दो प्रमुख आरोपित गिरफ्तार

पंचकूला (एजेंसी)। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में दो प्रमुख आरोपित रिभव ऋषि और अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 6 मार्च तक रिमांड मंजूर हुआ। जांच में अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस के कब्जे में लिए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी धन को फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए कई परतों में ट्रांसफर किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने स्वास्तिक, कैप को फिनटेक और एसआरआर प्लानिंग जैसी शेल कंपनियों का उपयोग किया। पहली परत में इन कंपनियों के कई बैंक खाते सामने आए, जबकि दूसरी परत में सैकड़ों अन्य खातों का नेटवर्क उजागर हुआ। पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस घोटाले की गहन जांच कर रही है। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच से और भी लिंक और पैसों के ट्रांसफर का रास्ता सामने आने की संभावना है।

गैलन में पेट्रोल-डीजल भरवाकर रख रहे लोग, यूपी में तेल खत्म होने की अफवाह

बाराबंकी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित कर दी है। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी कतारें लग गई हैं, लोग गाड़ियों के साथ-साथ ड्रम, कैन और गैलन लेकर तेल भरने पहुंचे। यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़राइल और ईरान के बीच तनाव और युद्ध की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण उत्पन्न हुई। लोगों के बीच यह धारणा बन गई कि अगर युद्ध लंबा खिंच गया, तब पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे दाम बढ़ सकते हैं या तेल खत्म हो सकता है। लखीमपुर खीरी में निघासन और भीरा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी गई। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे थे। सोशल मीडिया पर इन स्थितियों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें पंप कर्मचारियों के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पंपों पर लोगों के बीच जल्द तेल भरवाने की होड़ और धूप में लंबी कतारें स्पष्ट रूप से डर और बेचैनी को दिखा रही हैं। बाराबंकी में भी स्थिति अलग नहीं थी। श्री विष्णु नारायण फिलिंग सेंटर, आजगना, सद्दीपुर थाना जहांगीराबाद और तहसील फतेहपुर स्थित नेशनल ट्रेडिंग कंपनी पेट्रोल पंप पर किसानों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसानों ने खेती के मौसमी काम के लिए डीजल जरूरी बताया और इसे लेकर वे अधिक मात्रा में तेल जमा कर रहे हैं। कई किसानों ने कहा कि लाइन में डेढ़ से दो घंटे से खड़े हैं। आम लोग भी अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल भरवाने आए थे, लेकिन लंबे इंतजार की वजह से परेशान हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

ड्रग तस्कर इकबाल मेमन की मुंबई और दुबई में मौजूद 700 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की तैयारी

मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगौड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत विशेष पीएमएलए अदालत में याचिका दायर कर मुंबई और दुबई में दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मेमन और उनके परिवार की करीब 700 करोड़ रुपये की 15 संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने की मांग की है। याचिका में वर्ली स्थित संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू प्रॉपर्टीज शामिल हैं, साथ ही दुबई में करीब 15 संपत्तियां भी शामिल हैं, जिसमें बुर दुबई में होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट और बिजनेस बे और डीईसी टावर्स में एक दर्जन से अधिक वाणिज्यिक और आवासीय इकाइयां शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सीएस और डीजीपी ने लिया जायजा

हरिद्वार (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को प्रस्तावित हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैरागी द्वीप स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम की सुरक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की गहन समीक्षा की और संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू... तीन तरीकों से घर बैठे कराएं पंजीकरण

देहरादून (एजेंसी)। (ईएमएस)। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल एप या वॉट्सएप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को सुचारू रूप से संभाल सके। इस साल यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट इसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खुलने है। जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन तरीकों से होगा है। पहला, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना और यात्रा की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना। दूसरा, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल एप के जरिए अकाउंट बनाने के बाद यात्रा विवरण भरकर यात्रा पास डाउनलोड करना। तीसरा, वॉट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशनः 8394833833 पर 卐यात्रा卐 मैसेज भेजने के बाद चैटबॉट आवश्यक जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन पूरा करता है। उन यात्रियों के लिए जिन्होंने इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हरिद्वार और ऋषिकेश सहित कई प्रमुख स्थानों पर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 17 अप्रैल से होगी। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 भी जारी किया है। इस नंबर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यात्रा मार्ग, व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी जानकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव, नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद भाजपा सीएम की तैयारी

-नई सरकार में जेडीयू के हो सकते हैं दो डिप्टी सीएम

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना है, जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद संभाल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव के प्रभाव के बाद जिस दौर को नीतीश कुमार की राजनीति का युग माना जाता था, वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की चर्चा तेज हो गई है।

वैसे अभी नीतीश कुमार के इस्तीफे और नए सीएम के बनने में समय लगना तय माना जा रहा है। जानकारी अनुसार राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च तक चलने वाली है, जबकि नए राज्यसभा सदस्यों को 9 अप्रैल के बाद शपथ दिलाए जाने की बात कही जा रही। इस स्थिति में कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन में अभी करीब-करीब एक माह का समय लग सकता है। इससे पहले भाजपा और जदयू दोनों ही पार्टियां अपने-अपने विधायक दल की बैठक बुलाकर नेता का चयन कर सकते हैं, जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इस चयन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। भाजपा सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि रामनवमी (26 मार्च) से पहले बिहार में नई सरकार के गठन किया जाएगा और भाजपा का ही सीनीयर नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। रही बात जदयू की तो उसके कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना प्रबल है। नई सरकार के गठन के साथ ही इस बार पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है। इस आंकलन के मुताबिक लगभग 32 मंत्रियों के साथ नई सरकार शपथ ले सकती है। संभावित फार्मूले के अनुसार 14 मंत्री भाजपा से, 14 जदयू से और 2 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक-एक मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इस बार दोनों प्रमुख दलों की ओर से कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी चर्चा आम हो गई है। हालांकि सरकार गठन से पूर्व कुछ अहम विभागों को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान की स्थिति बन सकती है। फिलहाल कहा जा रहा कि जदयू ने विधानसभा स्पीकर और गृह विभाग पर अपनी दावेदारी जताई है। मौजूदा समय में स्पीकर का पद भाजपा के पास है और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। जदयू का तर्क है कि मुख्यमंत्री पद उनके पास होने के कारण इन पदों पर भी उनका अधिकार होना चाहिए।

दूसरी ओर भाजपा इन दोनों महत्वपूर्ण पदों को अपने पास ही बनाए रखना चाहती है। खासकर गृह विभाग 2005 के बाद पहली बार भाजपा के पास आया है। वहीं विधानसभा स्पीकर का पद भी सरकार की स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में सरकार गठन से पहले इन मुद्दों पर अंतिम सहमति बनना बाकी है।

19 साल की उम्र में बनी देश की सबसे कम उम्र की महिला सीए

-राजस्थान के झुंझुनूं की हैं राजकुमारी जिन्होंने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के झुंझुनूं जिले की प्रतिभाशाली छात्रा राजकुमारी पारीक ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अंतिम परीक्षा पास कर देश की सबसे कम उम्र की महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने महज 19 वर्ष 126 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले देश की सबसे कम उम्र की महिला सीए बनने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के मुरैना की नंन्दनी अग्रवाल के नाम था, जिन्होंने करीब 19 वर्ष 330 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। राजकुमारी पारीक ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। राजकुमारी की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण का अधिकांश हिस्सा अपने गृह जिले झुंझुनूं से ही पूरा किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झुंझुनूं में ही हुई। इसके बाद उन्होंने सीए की प्रारंभिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी भी स्थानीय स्तर पर करते हुए सफलता हासिल की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि राजकुमारी के पिता हेमंत कुमार पारीक अरुणाचल प्रदेश में मोटर पार्ट्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि उनकी माता सावित्री देवी गृहिणी हैं। परिवार ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम आज देश के सामने एक मिसाल के रूप में सामने आया है।

शराब घोटोले में बरी हुईं कविता का ऐलान तेलंगाना में बनाएगी नई पार्टी

-कहा- केंद्र सरकार ने एजेंसियों के जरिए हमें विच हंट का शिकार बनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत राष्ट्र समिति की पूर्व सदस्य और के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तेलंगाना में एक नई पार्टी बनाने जा रही हैं। कविता ने यह एलान तब किया, जब दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया था। बरी होने के बाद कविता तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर गईं। कविता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भगवान बालाजी के आशीर्वाद से हम जल्द ही तेलंगाना राज्य में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक के कविता ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया गया और कैसे केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए हमें इस तरह की विच हंट का शिकार बनाया जाता है। कविता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूरा देश और खासकर इस देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी होंगी। उन्हें विश्वास है कि तेलंगाना के लोग उन्हें आशीर्वाद जरुर देंगे। कविता ने बताया कि पार्टी तेलंगाना के लोगों के लिए काम करने वाली एक रीजनल पार्टी होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले के मामले के बारे में बात करते हुए के कविता ने इसे विच हंट कहा और केंद्र पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को टारगेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश में राजनीतिक विच हंट हुआ है, जिस तरह से हमें सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि हम एक अलग राजनीतिक पार्टी से हैं। यह इस देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका ने झूठ के इस जाल को देख लिया है और हम सभी को बरी कर दिया।

राज्यपाल आनंदबोस के अचानक इस्तीफे पर भड़की ममता... शाह के दबाव में लिया

कलकत्ता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल सीवी आनंदबोस के अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव से प्रेरित बताया और राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक बताया। सीएम बनर्जी ने कहा कि इस्तीफे के पीछे स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लिया गया कदम प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि बोस के जाने के बाद आरएन रवि, जो तमिलनाडु के राज्यपाल और पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले है। सीवी आनंदबोस ने 17 नवंबर 2022 को राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल नवंबर 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब साढ़े तीन साल के बाद ही इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक विश्लेषकों और राज्य प्रशासन को आश्चर्यचकित किया। लोक भवन के अधिकारियों ने बताया कि बोस ने दिल्ली से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजा। सीएम ममता बनर्जी ने इस फैसले को एकतरफा और राज्य हित के खिलाफ कदम बताकर कहा कि केंद्र को सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए।

वहीं, भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि राजभवन में बदलाव सामान्य प्रक्रिया है और बोस ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। इस घटनाक्रम का समय भी संवेदनशील है क्योंकि जल्द ही निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है।

बता दें कि आनंदबोस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और तृणमूल कांग्रेस के साथ उनके टकराव के मामले सामने आए। उनका इस्तीफा उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ के अचानक पद छोड़ने की याद दिलाता है, जिन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति चुने जाने के कारण राज्यपाल पद छोड़ा था। इस इस्तीफे ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ा दिया है और चुनाव से पहले सियासी माहौल को और गरम कर दिया है। कुल मिलाकर, बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, और इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

दिल्ली में बैठकर बोले ट्रंप के मंत्री- हम चीन की तरह भारत को नहीं देंगे आर्थिक फायदे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के प्रमुख भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा कि अमेरिका भारत की असीमित संभावनाओं को साकार करने के लिए उसके साथ काम करना चाहता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका पुरानी गलतियों से सीख चुका है। उन्होंने कहा- हम भारत के साथ वह गलती नहीं दोहराने जा रहे हैं, जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। चीन इन्हीं छूटों का फायदा उठाकर आज अमेरिका का एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया है।

क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा, हम उस व्यापार समझौते को लेकर उत्साहित हैं जो अब लगभग अंतिम चरण में है, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में असीमित संभावनाओं के द्वार खोलने का आधार बन सकता है। हम भारत और इन आर्थिक व वाणिज्यिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलतियां नहीं दोहराने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ यह कहकर की थीं कि, आप इन सभी बाजारों को विकसित कर सकेंगे, और फिर बाद में हम देखते हैं कि आप हमें ही कई व्यावसायिक मोर्चों पर पछाड़ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो कुछ भी करें वह हमारे लोगों के लिए निष्पक्ष हो, क्योंकि अंततः हमें अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना है, ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार की जवाबदेही अपने नागरिकों के प्रति है।

भारत ने मध्य पूर्व के इस बढ़ते विवाद में किसी भी पक्ष का समर्थन करने से बचते हुए पूरी तरह से तटस्थ रुख अपनाया है। इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच उस व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यभार संभालने के समय से ही बातचीत चल रही है। बता दें कि कई दौर की सकारात्मक बातचीत के बाद, वाशिंगटन ने पिछले महीने भारतीय सामानों पर टैरिफ (आयात शुल्क) को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

मौजूदा समय में जब अमेरिका भू-राजनीतिक वार्ताओं में टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रहा है, तब भारत अन्य देशों की तरह अपनी आर्थिक वृद्धि को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। भारत एक व्यापारिक भागीदार के रूप में केवल अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने व्यापार में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसी रणनीति के तहत, भारत ने कई अन्य देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ भी एक अहम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण ईंधन की आपूर्ति और भंडारण पर मंडरा रहे खतरे के बीच, अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। लैंडौ ने कहा कि अमेरिका भारत की अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर आदित्य और संजय राउत में अनबन... खबरों पर राऊत ने खुद दी सफाई

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र से शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा का टिकट कट गया है, उनके स्थान पर शरद पवार को उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी-एसपी के तिकड़ी के समर्थन से उतारा गया है। इस फैसले को लेकर शिवसेना यूबीटी के भीतर मतभेद की चर्चा जोरों पर थी, जिसमें खासकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत का रुख अलग-अलग बताया जा रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्टों बताया गया हैं कि आदित्य चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से मौका मिले, लेकिन अंत में संजय राउत की ही मंशा चली और शरद पवार को राज्यसभा भेजा गया। इन बातों को लेकर यह चर्चा भी उठी कि राउत ने आदित्य के इरादों पर भारी पड़ते हुए शरद पवार को कमिटमेंट दे दी, जिस वजह से प्रियंका का नाम पीछे रह गया।

अब संजय राउत ने खुद इन कयासों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि असल वजह पार्टी के राजनीतिक समीकरण थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्धव सेना के भीतर यह इच्छा जरूर थी कि प्रियंका चतुर्वेदी को दूसरा मौका मिले, लेकिन जरुरी वोटिंग नंबर नहीं थे और साथ ही पवार जैसे अनुभवी नेता ने स्वयं दावा कर दिया। इसलिए पार्टी को पवार का नाम समर्थन करना पड़ा। राउत ने कहा कि यदि समीकरण अनुकूल होते और पवार जैसे सीनियर नेता राज्यसभा जाने को ना चाहते, तब प्रियंका को 100 प्रतिशत मौका मिलता।

राउत का कहना है कि उद्धव सेना के अंदर प्रियंका को फिर से भेजने की इच्छा काफी प्रबल थी, लेकिन पार्टी के पास खुद के दम पर संख्या नहीं थी। जब शरद पवार ने दावेदारी पेश की, तब प्रियंका के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया।

राज्यसभा की इस दौड़ में महाराष्ट्र में कुल 7 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 6 पर एनडीए उम्मीदवारों का मजबूत संभावित जीत है। विपक्ष की एकमात्र संभावित जीत की सीट पर शरद पवार को उतारा है। वहीं भाजपा ने रामदास आठवले और विनोद तावड़े जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी राज्यसभा का मौका दिया है। संजय राउत ने कहा कि आठवले का टिकट पहले से तय-सा लगता था, और विनोद तावड़े को राज्यसभा भेजना भी संगठन में उनके लंबे सेवा और योगदान का प्रतिफल माना जा रहा है।

अदालत के आदेशों का पालन न करना, आजकल फैशन बन गया... सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेशों का पालन न करने और अवमानना याचिका दायर होने पर देरी से अपील दाखिल करने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जता दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि इसतरह के मामलों में सख्ती नहीं दिखाई गई, तब न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्?ला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि हाल के वर्षों में देखने में आया हैं कि अदालत के आदेशों का लंबे समय तक पालन नहीं होता और जब अवमानना याचिका दायर होती है, तब उसके बाद काफी देरी के साथ अपील या पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपील में देरी अपवाद होनी चाहिए, लेकिन अब यह करीब-करीब नियम बनती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते है। शीर्ष अदालत के अनुसार, जब कोई पक्ष जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करता, इस आचरण से न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह के मामलों में यह आचरण कई बार आपराधिक अवमानना की सीमा तक पहुंच सकता है। अदालत ने कहा कि यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में दृढ़ता नहीं दिखाते, तब देश के आम नागरिकों का न्यायपालिका में अटूट विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

अदालत के अनुसार, आदेश की जानकारी होने के बावजूद यदि कोई पक्ष जानबूझकर उस आदेश का पालन नहीं करता, तब वहां अवमानना के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही केवल अदालत में पक्षकार रहे व्यक्तियों तक सीमित नहीं होगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्?तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान की। मामला कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण से जुड़े आदेश के पालन न करने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेश लागू करने के लिए अंतिम मौका देकर 15 दिन का समय दिया है।